the Labour Minister to make a statement, because two lakhs workers are on strike and the entire economy of Berigal is affected by this.
'SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka): I support Shri Banerjee. I have also given notice of a Calling Attention. The matter is very important. So, it should be answered by the Labour Minister and not by Shri B. R. Bhagat.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Sir, I would suggest that the names of those hon. Members who have given notice of the Calling Attention should be included in the Short Notice Question because the subject is the same. Instead of the Calling Attention, you have been pleased to admit it as a Short Notice Question.

MR. SPEAKER: I quite agree with you.

घो शिव चन्द्र का (मघुबनो) : काल झ्रटेंशन मंजूर करना चाहिए था ताकि सब लोगों को मोका मिलता । एका मालूम होता है कि किसी सदस्य ने मंत्नी से बात की श्रौर ग्रापस में बात करकें तय कर लिया।

म्रध्यक्ष महोदय : में जब खड़ा हूँ तो श्राप मत बड़े होइये । As suggested here, I will ask the Labour Minister to reply to the questions. Then, the names of those four Members would be inciuded.

## LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL_contd. <br> Clause 2- contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the Lokpal and Lokayuktas Bill. Almost the whole of the time allotted for this Bill has been exhausted and only twenty minutes are left. We are still on clause 2. As far as possible, the time allotted by the Business Advisory Committee must be adhered to.

धी बि० प्र० मंडल (मघेपुरा) : श्रष्यक्ष महोदय, मैने जो संशोधन दिये हैं उसमें कुछ ग्रोरिजिनल टाइप के हैं। जैसे मने कहा ह कि on page 2, line 7 after "improper or" insert "discriminatory or". कहने का मतलब यह है कि भारतवर्ष में हम लोग दुनिया भर के फिरकों में बंटे हुए है, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन श्रौर प्रोविन्सेज में बटे हुए हैं श्रोर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान में बल्क ग्राफ दी पीपुल बैकवर्ड हैं ग्रौर चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे सर्विसेज हों, उसमें वे लोग नहीं हैं । इसलिए डिस्किमिनेश़न होता है, कास्टिज्म होता है, इसलिए बिल में यह स्पेसिफिकली प्रोवोज़न होना चाहिए कि जाति पाति के नाम पर जो पक्षसम्त होता है उसको भी लोकपाल ग्रोर लोकायुक्त देखें।

दूसरा मेरा संशोधन यह है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस बिल में शामिल करना चाहिये श्रोर प्रेसीडेंट को प्रधिकार होना चाहिये प्राड़म मिननष्टर के खिलाफ चार्ज ला सकें ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि मिनिस्टर श्रोर सेकेटरी को एक केंटेगरी में रखा गया है ग्रौर यह व्यवस्था की गयी है कि सेक्रटरी श्रोर मिनिस्टर के खिलाफ श्रगर कोई चार्ज लाया जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर लायेगा । में संशोधन करना चाहता हूं मिनिस्टर के खिलाफ जो कोई चार्ज हो तो प्राइम मिनिस्टर ला सकते हैं। श्रौर सेकेटरो के खिलाफ़ कोई च.र्ज हो तो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ला सकते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी ग्रोर मिनिस्टर को एक केटेगरी में रखना ठीक नहों है । हमको भी प्रदेश में मिनिस्टर श्रौर चीफ मिनिस्टर रहने का मौका मिला है इसलिए में जानता हूं कि मिनिस्टर ग्रोर सेऋेटरी को एक ग्रेड में रखना श्रच्छा नहों है । इसलिए बिल में जहां तक सेकेटरी का सवाल है उसमें कर दिया
[श्री बि० प्र० मंडल]
जाए कि उसकी कम्प्लेन्ट करने वाला मिनिस्टर ग्रफफ दी डिपार्टमेंट कन्सन्ड्ड होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा। ग्रौर जहां तक मिनिस्टर का सवाल है उसओे खिलाफ चार्ज लंगाने का ग्रधिकार प्राइम मिनिस्टर को होगा ।

बिल में काउन्मिल ग्रफफ मिनिस्टर्स श्राया है, लेकिन सदन में बहस के दौरान कहा गया कि प्राइम निनिस्टर निल नाट बो इनक्लूडेड । का क उनन्सिल प्राफ़ मिनिस्टन्न को कोई :-यी डै़़ी.नीशन बनाना चाहते हैं ? वाकई में काउन्सिल ग्राफ़ मिनिस्टर्स इनक्लूड्स दी प्राइम मिनिस्टर । जब भी कभी ग्रविश्वास का प्रस्ताव सदन में ग्राता है तो वह् काउन्सिल ग्राफ़ मिनिस्टर्स के खिलफ़ श्राता है, न कि प्राइम मिनिस्टर के । प्रधान मंत्रो कान्डन्सिल ग्राफ़ मिनिस्टर्स का प्रथम व्यक्ति होता है, यही परिभाषा सभी जगह मान्य है। तो जब विल में काउन्सिल अ्राफ़ fम्मनस्टर्स शब्द है ग्रौर उसं; खिलाफ लोकपाल ग्रोर लोकायुक्त को श्रधिकार हहोगा तो फिर मेरी समझ में नहीं ग्राता कि यह कहना कहां त़क उचित है कि प्रधान मंत्री ड़समें शामिल नहः होगा । यह कहां तक सही है ? इतलिए प्राइम गिनिस्टर को भी काउन्सिल श्राफ़ मिनिस्ट $\dot{f}$ के बाद इनमर्ट करना चाहिए- इनक्लूडिग दी प्राइम मिनिस्टर । श्रौर श्रन्त में जहां मिनिस्टर शब्द है वहां में पार्ालयामेंट़ी सेक्करी को इन्सर्ट करना चाहता हूं ।

मेरा लiन्ट तमेंडमेंट यह् है कि
श्रध्यक्ष महोंदय : ग्राप बंल लीजिए, ग्रलग-ग्यलग संशोधन मूव करने की जह्रत नहi है । श्रमेंडमेंट ग्राप $\because$ मूब्ड समझे जायेगे ।

भी बि० प्र० मंडल : मेरा यह कहना है कि में इससे कभी भी सहमत नहीं हूं कि प्राईम मिनिस्टर ग्रौर लीडर ग्राफ दी ग्रपोजीशन की राय से लोकपाल का श्रपोइंटमेंट हो । लोकपाल को पोलिटिकल इनफ्लूयेंस

से फी रखना चाहिये । प्राइम मिनिस्टर भी किसी पार्टी को रिप्रेजन्ट करते हैं ग्रोर लीडर ग्राफ़ दी श्रपोजीशन भी किसी पार्टी को रिप्रेजेन्ट करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि एक पैनल होना चाहिये नाम का, जिसमें एक नाम चीक़ जस्टिस ग्राफ़ इंडिया की तरफे से होना चाहिये, एक नाम कम्पट्रोलर ऐंड ग्राडिटर जनरल का होना चाहिए ग्रौर एक नाम स्तीकर ग्राद़. दो लोक सभा का होना चाहिये, ग्रौर तोन नामों के पैनल में से प्रेसीडेंट एक श्रादमी को लोफपाल श्रपोड़ंट कर ले । यह्टी मुझे कहना है ।

MR. SPEAKER: I will put the amendments now to the vote of the House. Should I put them together?

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI: (Krishnagar): Sir, I have an amendment to clause 2.
MR. SPEAKER: Now there is no use. Only a few minutes are left. Now I am going to rush through the Bill.
SHRI N. K. P. SALVE (Betul): Sir, if would not be fair to conduct the debate in a manner that certain important clauses will remain undebated in the House at all at this stage. Adequate time should be allowed on certain important clauses.
SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI: Sir. I may be given one minute to move my amendment.

MR. SPEAKER: Better not move it because it is going to meet the general fate.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara): We want to press amendment No. 91.

SHRI S. KUNDU (Balasore): Include 95 also.

MR. SPEAKER: I am putting amendment No. 91 to the vote of the House. The question is:

## Page 2,—

```
after line 12, insert-
    "(i) in the case of
        the Prime Minister
```

                    President of India
    (ii) in the case of
        members of Lok
        Sabha
            Speaker of Lok Sabha
        (iii) in the case of
        Members of Rajya
        Sabha
            Chairman of the Rajya
            Sabha" (91)
    The Lok Sabha divided:

Division No. 191
[12.45 hrs.

## Saxy

Ahmed, Shri J.
Amin, Shri R. K.
Banerjee, Shri S. M.
Bharati, Shri Maharaj Singh
Chaudhuri, Shri Tridib Kumar
Daschowdhury, Shri B. K.
Deb, Shri D. N.
Dwivedy, Shri Surendranath
Gowda, Shri M: H.
Jha, Shri Shiva Chandra
Joshi, Shri S. M.
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Kothari, Shri S. S.
Kundu, Shri S.
Kushwah, Shri Yaswant Singh
Limaye, Shri Madhu
Mandal, Shri B. P.
Mangalathumadam, Shri
Misra, Shri Janshwar
Misra, Shri Srinibas
Mohammed Imam. Shri J.
Molahu Prasad, Shri
Patel, Shri J. H.
Ram Charan, Shri
Samanta, Shri S. C.
Shah, Shri T. P.
Sharma, Shri Beni Shanker
Shastri, Shri Prakash Vir
Shastri, Shri Raghuvir Singh
Shastri, Shri Shiv Kumar
Suraj Bhan. Shri
Thakur, Shri Gunanand
Viswambharan, Shri P.

## NOES

Achal Singh, Shri
Aga, Shri Ahmad
Ahirwar, Shri Nathu Ram
Ahmed. Shri F. A.
Awadesh Chandra Singh, Shri
Azad, Shri Bhagwat Jha
Babunath Singh, Shr!
Barua, Shri Bedabrata
Bhagat, Shri B. R.
Bhagavati, Shri
Bhandare, Shri R. D.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhargava, Shri B. N.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Bohra, Shri Onkarlal
Bramhanandji, Shri Swaml
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandrika Prasad, Shri
Chatterji, Shri Krishna Kumar
Chaturvedi, Shri R. L.
Chavan, Shri Y. B.
Chaudhary, Shri Valmild
Choudhury, Shri J. K.
Dasappa, Shri Tulsidas
Dass, Shri C.
Dinesh Singh, Shri
Tring, Shri D.
Gandhi, Shrimati Indira
Ghosh, Shri Parimal
Girja Kumari, Shrimati
Hanumanthaiya, Shri
Hari Krishna, Shri
Hazarika, Shri J. N.
Himatsingka, Shri
Jadhav, Shri Tulsidas
Jagjiwan Ram, Shri
Jamir, Shri S. C.
Jamna Lal, Shri
Kamble, Shri
Karan Singh, Dr.
Kavade, Shri B. R.
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Shri M. A.
Kinder Lal, Shri
Krishna, Shri M. R.
Krishnappa, Shri M. V.
Kureel. Shri B. N.
Lakshmikanthamma,' Shrimati
Laskar, Shri N. R.
Laxmi Bai, Shrimati
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Malhotra, Shri Inder J.
Mane, Shri Shankarrao
Melkote, Dr.

Menon, Shri Govinda
Minimata Agam Dass Guru, Shrimati
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, IShri Bibhuti
Mishra, Shri G. S.
Mohsin, Shri
Mukerjee, Shrimati Sharda
Mukne, Shri Yeshwantrao
Murti, Shri M. S.
Palchoudhuri, Shrimati Ila
Pandey, Shri K. N.
Pande, Shri Vishwa Nath
Panigrahi, Shri Chintamand
Pant, Shri K. C.
Paokai Haokip, Shri
Parmar, Shri Bhaljibhai
Parthasarathy, Shri
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri S. D.
Poonacha, Shri C. M.
Raghu Ramaiah, Shri
Raju, Dr. D. S.
Ram, Shri T.
Ram Dhan, Shri
Ram Sewak, Shri Chowdhary
Ram Swarup, Shri
Rana, Shri M. B.
Rane, Shri
Rao, Shri Jaganath
Rao, Shri Muthyal
Rao, Shri Thirumala
Raut, Shri Bhola
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saha, Dr. S. K.
Saigal, Shri A. S.
Salve, Shri N. K. P.
Sanghi, Shri N. K.
Sanji Rupji, Shri
Sankata Prasad, Dr.
Sant Bux Singh, Shri
Sapre, Shrimati Tara
Savitri Shyam, Shrimati
Sayyad Ali, Shri
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Sethi, Shri P. C.
Shambhu Nath, Shri
Shastri, Shri Sheopujan

Sheth, Shri T. M.
Shiv Chandika Prasad, Shrt
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddayya, Shri
Siddheshwar Prasad, Shri
Sinha, Shri Mudrika
Sinha, Shri R. K.
Sonar, Dr. A. G.
Sonevane, Shri
Sureńdra Pal Singh, Shri
Swaran Singh, Shri
Tiwary, Shri D. N.
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Yadab, Shri N. P.
Yadav, Shri Chandra Jeet
MR. SPEAKER: The result of the division is:

## Ayes: 33; Noes: 120

The motion was negatived.
MR. SPEAKER: I shall now put alt the other amendments together to the vote of the House.
The other amendments* were put and negatived.
MR. SPEAKER: The question is:
"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill,
Clause 3-(Appointment of Lokpal and Lokayuktas.)
SHRI OM PRAKASH TYAGI:

## मुरादावाद

I beg to move:
Page 4, lines 25 and 26,-
for "or recommendation"
substitute-
"recommendation or investigation ${ }^{*}$ (47).

SHRI P. VISWAMBHARAN
(Trivandrum): I beg to move:
Page 4, line 6,
for "after consultation with"
substitute-"on the advice of"
(96).

[^0]NOES: Shri Ganga Reddy.
*Other amendments negatived: Nos 6, to $8,18,19,21,23,28,31,38,42,45$ 46,49 to 51,62 to 65,86 to $88,95,100,101,103$ to 106,113 to 115,118 , 119, 138, 143, 145 and 146.

## Page 4, line 7,-

"after "and" insert-after consultation with" (97).
SHRI B. P. MANDAL: I beg to move:-

## Page 4,

for lines 6 to 10, substitute-
*(a) the Lokpal shall be appointted from among the panel of three names in the following order:-
(1) one name to be given by the Chief Justice of India.
(2) one name to be given by the Speaker of Lok Sabha,
(3) one name to be given by the Comptroller and Auditor General of India." (122).

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga): I beg to move:

Page 4,—
after line 12, insert-
"Provided that no person who is or had been a Minister either in the Central Government or State Government or who is holding or had held an office of the Secretary or any other Government post shall be appointed as a Lokpal or Lolcayukta."
(140).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I leg to move:

Page 4.-

> after line 12, insert-
> "Provided further that no person who is or has been an active member of any political party shall be appointed as the Lokpal or a Lokayukta." (176).

मष्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि क्लाज नम्बर 3 जो कि लोकपाल तथा ओोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में है उसमें

बतलाया गया है कि प्रेसीबेंट उनकी नियुक्ति किन किन लोगों से सलाह करके करेगें।

मेंने घ्रपने इस ध्रमेंडमेंट के ह्वारा यह बाहा कि इस विधेयक के क्लाज नम्बर 3 में वेज 4 पर लाइन 25 पौर 26 में कोर "झ्रोर रैकमेंडेश्रन सन्सटीच्यूट" रैकमेंहेशन भोर इनवेस्टिगेशन"। मिने यह संशोष्दन इसलिए चाहा है कि यह लोकपाल तथा लोकायुक्त जोकि विभिस्न अ्रघिकारियों, संस्थानों श्रोर राज्य व केन्द्र के मंतियों के विर्द्ध प्रष्टाचार श्रादि की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल करेगें तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जोकि प्रष्टाचार सम्बन्दी मामलों की जांच पड़ताल करेगें उनका इम्पार्शियल होना तटस्थ होना परमावश्यक है ।

श्रध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि तटस्थता में यदि ग्राजकल कोई सबसे बड़ी बाधक चीज है तो यह राजनैतिक विचारधारा के लोग हैं, पोलिटिकल पार्टीज़े के लोग हैं जोकि साम्प्रदायिकता के ग्राधार पर, कास्ट, कीड श्रोर रैलीजन इन सबको भ्रपने सामने रखकर चलते हैं। ग्राजकल एक नई प्रकार की साम्यप्रदायिकता दिखाई दे रही है ग्रौर वह है राजनीति। स्मब किस्म भो राजनंतिक पार्टी से यदि कोई श्रादमी सम्बन्ध रखता है तो वह श्रन्य राजनंतिक पार्टी की ग्रच्छी या बुरी किसी भी बात को वह मानने को तैयार नहीं होता श्रोर उसकी भ्यालोचना तथा बुराई करने के : लिए हमेशा वह तैयार रहता है ।

इसी कारण हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रकार के नियम बनाये हैं कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी में कोई गवनेमेंट सर्वेटं भाग नहीं लेगा । गबर्नमेंट सर्वेट के किसी मी पोलिटिकल पार्टी में भाग लेने से रोकने का उद्देश्र्य यह है कि जितना भी . सरकार का कार्य हो वह निष्पक्ष हो भ्रोर न्यायपूर्वक हो श्रगर कोई सरकारी कर्मंचारी किसी पोलिटिकल पार्टी से ब्बन्ष जायेगा तो वह् उसके साथ रियायत जह्र
[भी थोन प्रकाण स्वागी]
करेगा 1 घगर लोकपाल या लोकागुक्त किसी मी राजनीकिक पार्टी का ऐक्टिव मेम्बर रह कुका है या हैं तो उसको इन पदों पर नहीं रबा जाना चाहिये।

थी रहुवोर निह भाल्त्री (वागपत): भाननीय सदस्य किस क्लाज पर बोल रहे音?

श्री भोम प्रकाग ह्यागी : क्लाज 3 पर। यह 3 (ए) में धाता है उसमें लिखा है कि :
'the Lokpal shall be appointed after consultation with the Chief Justice of India and the Leader of the Opposition in the House of the People.."

उस में मैने :ह जाड़ा हैं कि :
'Provided further that no person who is or has been an active member of any political party shall be appointed as the Lokpal or a Lokayukta."

शी रछुषीर सिह ज्ञासत्री : यह क्लाज 4 पर श्रायेगा। इसमें यह इरेलेंवेट है। उस में मैने भी ग्रमेंडमेंट दिया ठुग्रा है ।
MR. SPEAKER: I will now put all the amendments to clause 3 to the vote of the House.
Amendments Nos. 47, 96, 97, 122, 140 and 176 were put and negatived.

MR. SPEAKER: Now, the quesestion is:
"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.
Clause 4- (Lokpal or Lokayuktas to hold no other office).

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): I beg to move:

## Page 4, -

omit lines 34 and 35 (66)
Page 4,-
omit lines 38 and 39 (67).

घी रघुवीर सिह धात्री : "लोकपाल तथा लोकायुक्त विकेयक" की घारा 4 (ग) में वर्तमान के स्थान पर निम्नलिखित रहा जाय .
'ववह कमी किसी राजनैविक《ड का सक्षिय कार्यंकन्न न रहा हो।'

SHRI LOBO PRABHU: My good friend, Mr. Tyagi, has already supported my amendment that it is not proper for any one associated with a political party-and I would add, any one who is a Member of Parliament to be eligible to be Lokpal.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): These amendments have been rejected and clause 3 has been adopted by the House.

SHRI LOBO PRABHU: My amendments are to clause 4. I want lines 34 and 35 and 38 and 39 should be deleted because there should be an absolute bar on anyone who is associated with a political Party or any one who is a Member of Parliament. We have heard of defeated Members of Parliament appointed to different posts. It is something more than that that an acting Member should be appointed to this post. A Member of Parliament has a duty. He has been elected for a specific purpose. I prese both my amendments for the deletion of these two sub-clauses allowing exemption to a member of a political party and to a Member of Parliament.

बी द्रोम प्रकाइा स्यागो : में कहना चाहता हूं कि कोई ग्रादमी श्रगर किसी पोलिटिकल पार्टी का ऐक्टिव मेम्बर है या रह चुका है वो उससे किसी भी जांच के न्यायपूर्वक होने को श्रापा नहीं की जा सकती। मेरी तो ऐसी ही मान्यता है । सरकार ने इसी बात को दृष्टि में रखते हुए श्रपने सरकारी कर्मचारियों पर यह्र प्रतिबन्ध लगाया है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी वोसिटिकल पार्टी है

सम्बन्घ नहीं रखेगा । यही नहीं कि वह बोलिटिकल वार्टी का मेम्बर नहीं र्देगा बल्कि वह नहाईरेक्टली भी किसी गेिटिकल पार्टी से सम्बन नहीं रखेगा। ऐसी स्थिति में जो लोकपाल श्राप नियुक्ति करने जा रहे हैं यदि वह ऐसा श्रादमी होगा जो पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर रहा हो या किसी सरकारी कमिशन में रहा हो, सरकारी उद्योगों में रहा हो, तो वह श्रपनी पार्टी के घ्राषार पर एटमास्फिम्रर किएट करेगा । मै इन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन रांची के हेवी इंजीनिर्यारग कारपोरेशन में श्री मालत्रीय नियुकित हुए । वहां जाते ही उन्होंने इन्टक का जोर शुरू किया ग्रोर वहां की लेबर में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी।

सलिए श्रगर कोई भी झ्रादमी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्घित रह चुका है, तो उसको लोकपाल या लोकायुक्त के पद पर नियुक्त करना खतरे से खाली नहीं है। में इस श्रमेंडमेंट को पेश करत $T$ हूं ग्रौर झ्याशा करता हूं कि मंब्री महोदय स पर गम्भीरता से विचार फंशेंगे न्गर वह इस विधेयक की सफलता चाहते हैं।

धी रघुवीर सिस शास्त्री : मेंने भगना सशोधन इस्सलिए रखा है कि घ्राज जब कभी हम देश में निष्पक्ष व्यक्ति ढूंढ़ने लगते हैं तो श्राम तौर पर एक शर्त यह रखी जाती है कि वह व्यक्ति साम्प्रदायिक नहीं ोना चाहिये, किसी सम्प्रदाय विशेष में विश्वास करने वाला नहीं होना चाहिए । लेकिन हमारे राजनीतिक जीवन में इतनी खांचातानी हो गई है कि जितनी दल्शीव भावना सम्प्रदायों में है उससे कम राजनीतिक दलों में ग्रापस में नहीं है। ग्राप जिसको लोकपाल नियुक्त व.रेंगे वह कम से कम 55 यः 60 वर्ष की अ्रायु का तो होगा ! जो ग्रादमी 55 या 60 वर्ष तक किसी दल के साय रहा है, दल के साग उसका लगाव रहा है, दल के लोगो के साथ उसकी मिजता

रही है, उसके भन्दर उनके प्रति सद्भावना है श्रौर दूसरे दलों के प्रति उसके हृदय में दूसरी प्रकार के भाव हें, भ्रगर ऐसे व्यक्तित को नियुक्त कि.या जायेगा, तो उसका झुवाव श्रपने दल की श्रोर होगा। कोई भी छोटी या बढ़ी छश्यू हो, छोटी या बड़ी नियुक्ति हो, जिस दल के हाथ में नियुक्ति करने का श्रधिकार होता है वह सोचता है कि उससे सरकारी दस का लाभ होने बाला है या नहीं। जो भी लोक पाल को नियुक्त करेगा वह यह देखकर नियुवित क.रेगा कि इससे सरकारी दल को हानि हो रही है या लाभ हो रहा है-। इससे लोकपाल ग्रीर लोकायुक्त की निष्पक्षता पर घ्रांच ध्याये। इसलिए में कहना चाहता हूं कि जब भ्राप लोकपाल निर्युवित क.र रहे हैं तो लोष:पाल की नियुक्ति कराइये दलपाल की नियुक्ति न कराइये। भगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो इस विधेयक के पीछे जो भावना है वह् सारी नष्ट हो जाऐगी।

मेरा श्रनुरोध यह है कि इस में श्राव यह भ्रवभ्य रक्षें कि वही व्यक्ति लोकपाल निगुक्त किया जाये जिसका क.भी किसी दल के साथ कोई सम्बन्घ न रहा हो, श्रमर प्राप चाहते हैं कि इस पद पर निष्पक्ष व्यक्ति रखा जाये। जिस प्रकार श्राप क्रसाम्र्रदायिक व्यक्ति कहते है उसी प्रकार यहां यह होना चाहिये कि जो भी नियुदित श्राप करें वह पोलिटिक्ल नियुवित नहीं होनी चार्हये।

घी विध्धा घरण शुक्स : ग्रघ्यक्ष मह्रोदय जो भावनायें माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं こनसे में पूर्ण सहमत हूं । सवाल यह है कि इस में किस प्रकार का प्रावधान करना चाहिये जिस से यह भावनार्यें पूरी हो सरें इस के लिए हम लोगों ने प्रावधान में कहा हैं कि जिस व्यववत को द्नन में रखना हो उस को केवल प्रघान मंत्नी की तरफ से न रखा जाय बहिक जो हमार विगेधी दल के नेता

## 

हैं, श्रीर यदि एक नेता न हो तो समस्त विरोधी दल के लोग एक व्य.क्त को डांट लें , उससे परामर्श करके रखा जाये । इसके साथ साथ हमा चोफ जस्टिस से भी पूछा बार भ्रोर उ से पूछने के बाः लोकपाल को नियुक ! किया जाय । इस का भतलब यह होता है कि ऐसा व्यकित लिया जायेगः जिस के बारे मे लगभग संस्गंस .f: हो।

### 13.03 hrs .

यदि हम किसी तरह का उस में बन्बन लगाना चाहें कि वह राजनींतव: दल सं
 श्रौर उसको चाहे सभी तों पसन्द करतंत हों. चीफ जस्टिस मी सन्द कंरें, विरोती दल के नेता भी पसन्द करें, राजनीतबः दल जो केन्द्र में है प्रोर प्रन्त में है, वह भी पसन्द :रें, तो बूं.क वह दो तोन साल या दस बीस साल तक किसी राजनोंतक єल में रह कुका है लेकिन हर तरह से पोग्य है म्रोर उतनो इस वास्त श्र्योग्य ठहरा दिया जाए कि वह किमो राजोतेक दल का सदस्य रहा है, दो में समझता हूं यद डोळ नहीं: होगा। इस तग्ह का कोई मो संगोषन स्वाकार करने में में भ才 ब हैं ।
SHRI LOBO PRABHU: What about Member of Parliament'? The hon Minister has not replied to my question. He has not replied to my objection that a Member of Parliament should not be eligible for appointment as Lokpal.
SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA:
We have provided that if a Member of Parliament is appointed, he will vacate his seat.

SHRI LOBO PRABHU: He is bound to do that.

SHRT S M BANERJEE (Kanpur): Why should he object? We are going to recommend his name;

MR. SPEAKER: I shall now put amendments Nos. 66, 67, and 193 to vote.

Amendments Nos. 66, 69 and 195 were put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:
"That cause 4 stand part of the Bill".

The motion was adopted.
Clause 4 was added to the Bill.
MR. SPEAKER: We shall take up clause 5 after lunch.

### 13.03 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunck till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.
[SHRI M. B. RANA in the Chair.]

## LOKPAL AND LOKAYUKTAS BIIL -contd.

Clause 5.-(Term of office and other conditions of service of Lokpal and Lokayukta).

SHRI RAMAVATAR SHASTRI
(Patna): I beg to move:
Page 5 lines 35, and 35,-after "Government" insert 'or private' (41).

Page 5, line 36, add at the end"or companies or societies owned or controlled by big business houses (148).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 5, line 36,-add at the end"or in companies or societies owned by big business houses". (178).

MR. CHAIRMAN: We have exhausted the time allotted.

I shall put to vote amendments Nom. 41, 148 and 178.

Amendments Nos. 41, 148 and 178 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:
> "That clause 5 stand part of the Bill."

> The motion was adopted.
> Clause 5 was added to the Bill.
> Clause 6- (Removal of Lokpal or Lokayukta).

MR. CHAIRMAN: There are mendments, $15,48,180,181$ and 182.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani): I beg to move:

Page 6, line 33,-for "by each House of Parliament".
substitute "by the House of People" (15).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 6, lines 22 and 23,-
for "on no other ground" substitute "malpractice" (48).

Page 6, line 22,-
after "misbehaviour" insert.
"misconduct" (181).
Page 6, lines 22 and 23,-
omit and on no other ground." (182).

थी शिव चन्त्र का : सभापति महोदय, कलाज 6(3) में लोकपाल ग्रौं लोकायुक्त को उन क वद से हटाने के सम्बन्ध में यह ठ्यवस्था की गई है कि संसद् के दोनों सदनों के बहुम; चाएव गष्ट्र्पति को इस श्राशय का एड्रेस दिये जाने पर उन्हें हटाया जा सकेगा 1 में निवेदन कर्ना चाहता हूं कि लोकपाल द्रोर लोकायुक्त की नियुक्ति है सम्बन्घ में क्लाज 3 में बह व्यवस्था की गई है कि इस विषय में लोक सभा में श्रापोज़ोघान के नेता के साथ परामरं किया जायेगा। उस बलाज मे राज्य सभा का कोई उल्लेख नहीं है । मे रा कहना यह है कि जब लोकपाल

иोर लोकायुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ष में केवल लोक समा का जिक्र किया गया है, तो फिर उन्हें बर्सास्त करने के मामले में राज्य समा को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है । जब लोक समा उन्हें बहाल करती है, तो उसी को यह पावर होनी चाहिए कि वह उन्हं हटा सके। अ्रपने संशोषन संख्या 15 द्वारा में यह चाहता हूं कि संसद् के दोनों सदनों के बजाये केवल लोक सभा द्वारा बहुमत से मेजे गये एर्देस के श्राषार पर लोकपाल या सोकायुक्त को हटाया जा सके।

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): I move my amendment No. 180:

Page 6,—
for lines 22 and 23 , substitute-
'President on the ground of misbehaviour and incapacity, and that he has allowed himself to be influenced by any Minister in taking decisions with regard to any matter under investigation by him, and on no other ground." (180).

The basic point is that if the Lokpal allows himself to be influenced by a Minister, that should be a ground for his removal. It should not be necessary to have a two-thirds majority for his removal; a simple majority should be good enough. Instead of both the Houses concurring in it, if either of the Houses decides that the Lokpal should be removed by a simple majority, he should be removable.

घी घ्रोम प्रकाश त्वागी : भ्रम्यस्ष महोदय भै एक छ्बोटा सा प्रशन पूर्ंगा थोडा शंका समाधान के लिए। इस क्लाज 6 में भाप न कहा है :
"Subject to the provisions of article 311 of the Constitution, the Lokpal or a Lokayukta may be removed from his office by the President on the ground of misbehaviour or incapacity and on no other ground.".
[श्री घोम प्रकाश त्यागी] में पूद्बना चाहता हूं कि मिसविहेवियर, हनकपेसिटी यह तो ठीक है लेकिन भ्रगर करप्ट है वह तो ? म्राप यह कहते हैं कि नो प्रदर प्राउन्ह, यह जो पीछे जोड़ देते हैं, यह गलत है 1 कोई दूसरी भी शिकायत हो सकती है, दूसरे प्राउन्ड भी हो सकते हैं। ग्राप ने सिर्फ दो चीजों को ले लिया है मिसबिहेवियर और इनककेपसिटी लेकिन श्रगर वह करष्ट हं या इस प्रकार की भाईबन्दी की बात उसने की है, दुनिया भर की बातें हैं, श्रनेक बातें हो सकती हैं, तो बैसी हालत में न तो श्रोर प्राउन्ड किसी के लिए भी बाइंडिग हो जाएगा । इस प्रकार के लोकपाल म्रोर लोकायुक्त को इतना एबव श्राप रस देंगे कि जिस से कोई उस को हटा न सके तो कल श्राप के लिए मुर्किल हो जायगी । इसलिए नो भ्रदर प्राउन्ड को श्राप हटा दीजिए।

SHRI S. M. BANERJEE: I just want to say a word....

MR. CHAIRMAN: The hon. Member does not have any amendment.

SHRI S. M. BANERJEE: I want to support his amendment.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has understood the point. Now, let him reply.

SHRI S. M. BANERJEE: I am in your hands.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: If hon. Members would carefully see the clause they will see that misbehaviour on the part of the Lokpal would embrace all these questions that hon. Members have in mind. For instance, getting influenced by anybody including a Minister or being corrupt tantamounts to misbehaviour. As a matter of fact, we have used the language of article 124(4) of the Constitution, and since we are equating the Lokpal with the judges of the Supreme Court, whatever grounds have been mentioned for the removal of Supreme Court judges have been
mentioned for the removal of the Lokpal also. I would, therefore, request hon. Members not to press their amendmens as far as this particular matter is concerned.

Shri Shiva Chandra Jha wants that only the lower House should have the autherity to proceed against the Lokpal. Here, again, I would invite his attention to the Constitution where removal of the Supreme Court judge requires $a_{n}$ address to be presented by both Houses of Parliament and not only the lower House. In this case also, we have kept the provision that both Houses of Parliament should be consulted, so that both Houses are kept in the picture whenever the necessity for removing the Lokpal might arise.

SHRI S. S. KOTHARI: It should be by a simple majority.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Therefore, I would not be in a position to accept any of these amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendments to clause 6 to vote.

Amendments Nos. 15, 48 \& 180 to 182 were put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That clause 6 stand part of the Bill".

The motion was adopted.
Clause 6 was added to the Bill. clause 7- (Matters which may be investigated by Lokpal or Lokayukta.)

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka): I beg to move:

Page 6, line 40, after 'Minister' insert-'including the Prime Minister'. (24)
SHRI P. VISWAMBHARAM: I beg to move:

Page 6, line 40, add at the eno 'A Member of Parliament'. (98).

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move:

Page 7, after line 28, insert:
"(5) Subject to the provisions of this Act, the Lokpal may investigate in the manner to be prescribed under the rules the assets held by Ministers and Secretaries to find out if the assets so held are disproportionate to the lawful income of Ministers and Secretaries". (149).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move :

Page 6, after line 39, insert "(i) the Prime Minister or the Deputy Prime Minister". (188)
SHRI S. S. KOTHARI: I beg to move:

Page 7, after line 28, inseri"(5). The Lokpal may investigate the assets held by Ministers and Secretaries to ascertain if the assets so held are disproportionate to the lawful income of the Ministers or Secretaries.". (188).

धी रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट कहना है, मेरा जो संशोघन है उसकी 28 वीं लाइन के बाद एक नया पैरा हम जोड़ना चाहते हैं जिस का श्राशाय यही है कि जो मिनिस्टर या सेक्रेटरी होते हैं उस समय जो उन की सम्पत्ति का व्योरा होता है ग्रोर श्रागे चल कर बहुत से लोग बहुत सा घन ग्राजित क.र लेते है तो में बहुत जट रदा का फर्क हों तो इस संशोधन के मुताबिक लोकपाल को यह श्रfिकार होना चाहिए कि वह उस में दखल दे,उस की जांच करे ग्रोर ग्रप नी सम्मति दे, इसरिए इस को में इस में जोड़ना चाहता हूं। श्राप जानते हैं हमारे बिहार में कुछ पुराने पत्रियों पर मुकदमें भी चल रहे हैं कि पहले उन की कितनी सम्पति थी ग्रौर बाद को उन्होंने कितनी सम्पत्ति श्र्रजजत कर ली । यहु बात सब जगह खुली हुई है । इसलिए मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार

करने में कोई हिचक मन्त्री महोदय को नहीं होना चाहिए क्योंकि भर् यह बात साफक. हो जाय कि बहुत फर्क है उन की मूल सम्पत्ति घौर मिनिस्टर श्रौर सेकेटरी होने के बाद जो उन की सम्पत्ति हुई दोनों में तो उस की जांच करने का श्रधिकार लोकणाल को होना चाहिए जिससे जो गलत तरीके से घन श्रजजत किया जा रहा है उस को रोका जाय म्रोर साथ ही साथ उन के च्लिलाफ कार्यंवही की जाय। इस में कोई एसं बात नहीं है जिसे मंत्री महोदय स्वीकार ने करें।

SHRI S. S. KOTHARI: When corruption is rampant, it is not possibie generally $t_{0}$ catch the offenders redhanded. But assets are something which could be ascertained with definiteness. If it is found that the assets of a secretary or a Minister are disproportionate to his income, he can easily be apprehended and it should be within the ambit of the Lokpai's powers to investigate into the natter, and wherever there is any suspicion he should go into the details and he can also take the assistance of experis and others. If the assets are found to be disproportionate, he can make a recommendation that necessary action should be taken. He can call upon the person concerned to explain how he acquired those assets, and if he cannot explain them satisfactorily, action can be taken. Actually, it is a lacuna which would be removed and I think the hon. Minister should accept this amendment.

## SHRI P. VISWAMBHARAM: Clause 7(1) says:

Subject to the provisions of this Act the Lokpal may investigate any action which is taken by, or with the general or specific approval of-
(i) a Minister or a Secretary; or.
My amendment seeks to include 'Member of Parliament' also in this clause. It is not fair on our part to exclude Members of Parliament froms.
[Shri P. Viswambharam] the purview of this Bill. If we ourselves do not submit to be scrutiny of the Lokpal, then we have no moral right to pass this Bill. Therefore, I have moved this amendment. Since this is going to be a model legisiation for the States also, we should set up an example to the States. Therefore, I would urge the hon. Minister to accept my amendment.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA:
I would invite the attention of hon. Members, particularly Shri Ramavatar Shastri and Shri S. S. Kothari to clause 2 (b) which gives the definition of the term 'allegation'. If the Bill did not contain any provision to cover the contingency that the hon. Members have in mind, I would have had no hestitation to accept the amendment, but according to this definition of allegation, such matters are completely cove:ed under this Bill. The Lokpal can definitely look into the disproportionate assets of secretaries and Ministers under this particular power that has been given. Further, under his own suo motu powe s which have been given to him under clause 11 (1) and clause 11 (2). he can call for the statement. If such statements are not available on record or anywhere else, from the secretaries and Ministers and look into those things and also go into the matter. So, all these matters which the hon. Members have in their mind are already covered under the existing provisions, and therefore, it will not be necessary to accept any of the amendments. (Interruption). I said I would have been happy to sccept it if it was not the e. It is already there and we should not make such an important pice of legislation cumbersome and repetitive. Therefore, I hope the hon. Members will not pres3 the amendment because it is already there. It already finds a place there.

Regarding Members of Parliament, this matter was very deeply considered. You. Sir, were the Chairman of the Joint Committee, and we considered this matter quite deeply in
the Joint Committee, and it was ultimately found that it would not be proper and it will not fit in the scheme of things if Members of Parliament were to be included in the purview of Lokpal and Lokayukta. Therefore, we took a decision not to include Members of Parliament in the purview of Lokpal. Therefore, I am ungble to accept that amendment also.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendments to clause 7 to the vote.

Amendments Nos. 24, 98 149, 183 \& 185 were put and negatived
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 7 was added to the Bill.
Clause 8-(Matters not subject to investigation.)
SHRI LOBO PRABHU: I move:
Page 8, omit lines 8 to 10. (75) SHRI N. K. P. SALVE: I move:

Page 7, for lines 36 to 40, substitute
"Provided that a remedy before the High Court or the Supreme Court to issue directions, orders or writs under article 226 or article 139 respectively of the Constitution in respect of any griev. ance will not be deemed to be a remedy within the meaning of item (b) of sub-section (1):

Provided further that the Lokpal or Lokayukta may conduct an investigation notwithstanding that the complaint had or has such a remedy if the Lokpal or as the case may be the Lokayukta is satisfied that such person could not or cannot for sufficient cause have recourse to such remedy:

Provided further that in case the Tribunal or the court of law. as the case may be, before whom remedy against an action is sought makes an Order in favour
of the complainant and the tribunal or the court of law, as the case may be, making such urder in favour of the complaint is not competent to proceed again3t, the public servant on whose action they have made such order, a complaint against such action, shall, notwithstanding caluse (b) of sub-section (1), be entertained by the Lokpal or Lokayukta if the same, prima facie, indicates either mala fide, corrupt, perverse grossly negligent act on the part of a public servant involving gross abuse of his powers and authority." (89).

MR. CHAIRMAN: Shri Lobo Prabhu. Just one minute. We have already exceeded the time.

SHRI LOBO PRABHU: This is rather an important amendment. I would not take one extra minute. Now in this amendment, I have said that the provision which exempts from the jurisdiction of Lokpal mentioned in clause (k), subclause (iv) should be deleted.

I would like to refer the Minister to clause ( $k$ ), sub-clause (iv) of clause 2. This clause includes an offcer employed in any local authority, in any corporation, any Government company, any society. (Interruption). The measure of corruption is as high in these corporation and local bodies. I would like to know why, when you are concerned with corruption, you are exempting an area which is so heavy, so rich, with corruption.

I will ask the Minister another question. If it was not the intention to include these classes under the jurisdiction of the Lokpal, what is the nurpose of this clause (k), subclause (iv)? There was no necessity at.all to designate these officers: either vou completely delete this class of officials or place them under the jurisdiction of the Lokpal.

I need not say the Minister must be very tired already of rejecting the amendments, but I am not tired of pressing my amendments. Amendments are a legitimate part of the pro-
cess of legislation. Is the Minister thinks that no amendments should be accepted, I would like him sometimes to wonder why he has not objected to the very structure of our procedure here, because, to turn down every amendment from every Member does not do credit to this House. I may add that legislation is a most important part of the work of this House. If you do not take the co-operation of the Opposition, if you think what has been put to you by your officers is the last word, you are making a very fatal mistake in respect of the functions of this House.

SHRI N. K. P. SALVE: The amendment which I have moved seeks to provide two provisos n addition to the one which is already there in the Bill. The entire purpose of the two provisos is to delete the unintended effect which might come as a result of drafting. It is stated in the Bill that no complaint can be made of a grievance if the complainant has any remedy by way of proceedings in a court of law. My first proviso seeks to make it clear that even if there is a remedy open to the complainant by way of a writ petition in a High Court, it should be open to the person to go to the Lokpal or Lokayukta instead of a writ petition because of the difficulties involved in filing a writ. The subject-matter in mary cases would be almost the same. Yet, if a remedy is available to a person by way of a writ petition, he should not be compelled to go to the High Court by way of a writ, even though that right is available to him; it should be open to him to go to the Lokpal or Lokayukta instead of a court.

SHRI SRINIBAS MISRA: Nobody can compel him to go to the court.

SHRI N. K. P. SALVE: Suppore a rem?dv by way of a writ is zvailable. They may not entertain the grienvance or complaint on the ground that a remedy is available. It is likely to happen. At least, that is my view of the matter.

Secondly, we have left judiciary entirely out of the purview of this Bill. Now we are likely to leave out a very important section of the executive; I am worried about the Income-Tax Department, Sales Tax Department, Customs and Excise. In regard to income-tax there is remedy provided in the tribunal and in the High Court; High Court is the last court, so far as questions of law are concerned and the tribunal is the last one, so far as question of facts are concerned. It is more than iikely that several questions will arise in respect of which one cannot go to the tribunal or the High Court and there is no remedy available before an aggrieved party. Now we have defined "grievance" as undue hardship and injustice. The very same definition comes also under "allegation"-undue harm or undue hardship to any person concerned. If there is any undue harm or undue hardship to any party, he will still not be able to go to the Lokpal and the income-tax officer will go on merrily doing whatever he wants. We are collecting Rs. 2,200 crores by way of direct and indirect taxes. So, it is absolutely imperative that the Lokpal and the Lokayukta must have jurisdiction over those people who are collecting these direct and indirect taxes. If, for any reason, the Home Minister considers that officers of income-tax, sales-tax, customs and excise are already covered by clause 8 (1), I would request him to consider one point. We have been having ho many litigations on account of improper drafting because the intentions of the legislature are not brought out to the statute book in a proper and apt manner. Therefore, in order to avoid any such unnecessary litigation, if what I am saying is already there in the statute hook, and if it is not there, to rope in ail those people who are responsible for collecting direct and indirect taxes, these two provisions must also be added.

SHRI VIDYA CHARAN SHUK! A: The amendment moved by Shri Salve
has been very carefully considered by us. We wanted to find out whether we can improve upon this scheme. But, as far as his fears are concerned, we found that they are already covered by the provisions of this Bill. As he himself was stated, whereas grievances are concerned, there are iemedies otherwise available by a writ petition or by going to a tribunal. The applicant can go and agitate the matter before them. But, as far as the allegations are concerned, they come under the purview of this Bill. So, if there is any allegation that an assessee wants to make in regard to any tax matter against the Income-tax Officer or the Assistant Commssioner of Income-tax or the sales-tax Officer, he can still go to the Lokayukta; there is no bar. If he has a srievance of over-assessment, or wrong assessment against the Income-tax Officer, he can certainly appeal to the superior authority from the Incometax Officer he can go to the Assistant Commissioner from the Commissioner of Income-tax to the Tribunal. He can also go by a writ petition to the High Court.

Therefore, I do not think it would be possible for us to include all those things and widen the area of the Lokpal and the Lokayukta in such a manner that it becomes completely impossible tc work. Therefore, wherever there is a remedy available aganist grievances, we have not included it here but as far as allegations are concerned, all allegations are included in this and anybody who has any allegation against any member who is working for the Union Government can come up to the Lokpal and agitate the matter before the Lokpal or the Lokayukta as the case may de.

Shri Lobo Prabhu should not get disheartened if his amendments are not found acceptable by us. It is not that we do not want to accept any amendments. Shri Lobo Prabhu should know that in the Joint Committee dozens and dozens of amend-
ments moved by hon. Members belonging to the Opposition parties were accepted by us to this Bill and we $\varepsilon$ re thankful to them for having gone so deeply into the matter and suggested such useful amendments. Having done that, it is not right for any hon. Member to say that we reject amendments because we are completely closed to accepting amendmens from hon. Members. Wherever any amendment is found suitable and useful, we would definitely accedt it. Shri Lobo Prabhu has taken a lot of peins in moving his amendments and some of his amendments are useful; but if they are already covered under the provisions of the Bill, I am not in a position to accept them.

His amendment here says that persons belonging to the public sector undertakings or the Corporation and other things in the Union territory should be covered by it. They are covered as far as allegations go but they are not covered as far as grievances are concerned. If there is a tender awarded by a public sector undertaking and there is some difficulty about the tender, persons who have not been awarded the tender can go to the higher authority; they can come to the Government and can even go to the court and challenge that kind of discrimination on various grounds that are provided for in the laws and in the Constitution; but if there is any allegation against any of these people which Shri Lobo Prabhu has in mind, that is already covered by this Bill for the allegations of the categories which Shri Loo Prabhu has indicated are already covered under the Bill. Therefore the intention that he has in mind to fight corruption or to discourage such tendencies among public servants in Union territories and in the public sector organisations is already covered under this and I do not think it is necessary for me to accept any of these amendments.

SHRI N. K. P. SALVE: In view of the explanation of the Home Minister I seek leave of the House to withdraw the amendment.

SHRI LOBO PRABHU: I also wish to withdraw my amendment.

MR. CHAIRMAN: Have the hon. Members the permission of the House to withdraw their amendments?

## Amendments Nos. 75 \& 89 were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN:The question is:
"That clause 8 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 8 was added to the Bill
Clause 9-(Provisions relating to complaints).

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Sir, I move:
Page 8, line 35,-

> after "allegation", insert"anonymous or" (17)

SHRI SRINIBAS MISRA: Sir, I move:

## Page 9, line 7,-

for "place" substitute "institution" (52)

Page 9, line 10,
for "place' substitute "institute" (53)

Then, under rule 79 I may be permitted to move amendment No. 54 in a modified form. It was submitted in one form but now I want to make some verbal changes. I move:

Page 9, line 10,add at the end.-
"and the Lokpal or Lokayukta as the case may be, may, if satisfled that it is necessary so to do, treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of sub-section (2)". (54)
SHRI B. P. MANDAL: Sit, I move:
Page 9,-
after line 10, insert-"Provided that no stamp or fee of any type shall be charged for filing any complaint." (132).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Sir, I move:

## Page 9,-

after line 10, insert-"Provided that no stamp duty or fee of any type shall be charged for filing any complaint." (188).

SHRI SRINIBAS MISRA: My amendments Nos 52 and 53 are almost the same amendments. According to the previous provision in this Bill, persons who are in custody will write the letter to the Lokpal and the Lokayukta and that letter will be forwarded by the person having their custody. It was strange that originally the drafting was:-

> "Notwithstanding anything contained in any other enactment, any letter written to the Lokpal or Lokayukta by a person in police custody or in a jail or in any asylum or any place for insane persons."
Previously, was "receptacle" in place of "place", as if our insane persons were kept inside a vat. The Joint Committee changed it $t_{0}$ 'place". My submission is that that is not appropriate. Perhaps the hon. Minister will concede that there are benches in parks and many insane and mad persons go and live there. Will it be necessary for the keeper of the park to forward his letters? So, I have tried to suggest that in place of "place", the word "institution" should be substituted. The proper word is 'institution'. Wherever insane persons are kept under custody or in the care of somebody, there is an institution, not a place like river bank or park where some insane persons collect and there is a PWD officer-incharge or somebody. It is not that. It should be an institution.

Then, my amendment No. 54 in modifled form is like this. On P. 9, line 10 , -add at the end, "and the Lokpal or Lokayukta as the case may be may, if satisfled that it is necessary so to do, treat such letter as a complaint
made in accordance with the provisions of sub-section (2)". What I mean to suggest is that whencver such a person writes a letter, it shall be forwarded and whenever theLokpal or Lokayukta thinks that he can act upon that letter, he will treat it as a complaint.

It is a very simple and clear amendment and, I hope the Government will accept it.

घो निष चन्द्र का : सभापति महोदय, मेरा संशोषन क्लाज़ 9 (बी) में है :

Page 8, line 35,-
after "allegation", insert-"anonymous or"
शब्द "एलिगेशन" के बाद म शब्द "एनानिमस घ्रोर" जुड़वाना चाहता हूं । लोकपाल श्रोर लोकायुक्त के सामने जो शिकायत की जायेगी, कोन अ्रादमी शिकायत कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, किस तरह से लोकपाल श्रोर लोकायुक्त के द्वारा जांच की जायेगी, उसके मुताल्लिक यह है 1 जो शिकायत करने का तरीका रखा गया है उसमें है :
"Every complaint shall be madein such form and shall be accompanied by such affidavits.... as may be prescribed."

तो यह तरीका ठीक नहीं है 1 बहुत से लोग समाज में सराबियों को जानते हैं, बड़े ग्रफसरों घ्रोर मिनिस्टरों की खराबियों को जानते हैं लेकिन उनकी कहने की हिम्मत नहीं होती है । श्रगर श्राप इसको इसी तरह से रखते हैं तो शायद कोई भी शिकायत सामने न श्रायें। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एनानिमस षम्द भी इसमें जोड़ दिया जाये, श्रगर कोई गुप्त नाम से भी लोकपाल, लोकायुक्त को बिकायत कर देता है तो वे उसकी जांच कर लें कि प्राइमा फैसी केस बनता है घ्रोर घगर बनता है तो भागे उसकी जांच होनी चाहिए। इस रास्तें को मी भ्रस्तयार किया जाना चाहिए । यदि ध्राप इसी बात को रसे

हैं कि स्टफाइड्ये एफिडेविट सगाये तो फिर हो सकता है कि जितनी शिक्रायतें श्रानी चाहिएं उसमें से 5 परसेन्टं ही श्रायें घ्रीर 95 परसेन्ट शिकायत्तें वैसे ही रह जायं। भाज दिल्ली में सभी लोग जानते हैं कि सिन्डीकेट की वजह से कितनी खराबियां हो रही हैं लेकिन किसी की सिन्डीकेट के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। घस लोकसभा के श्रन्दर ही जो सदस्य हैं उनके दिस में रहता है, वे जानते हैं कि फलां मिनिस्ट र खराब काम करता है, उसके खिलाफ रिकायत होनी चाहिए लेकिन एफिडेविट लगाकर वह देना चाहते नहीं हैं। इसीलिए मैंने एनोनिमस का रास्ता रखा है। इससे ग्रापका काम ज्यादा श्रच्छ्धा चलेगा, ज्यादा शिकायतँ सामने श्रायेंगी ग्रौर उस ग्रादमी के लिए घबराने की भी जहूत नहीं होगी। इससे भापके इस बिल का मकसद़ पूरा हो जायेगा। इसीलिए में जब्द एनानिमस को इसमें जुड़बाना चाहता हूं ।

श्री भ्रोम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि लोकपाल श्रोर लोकायुक्त को कम्पलेन्ट करने का तरीका बहुत सरल ग्रौर सीधा होना चाहिए जिससे जिसको जो भी रिकायत करनी हो वह ग्रासानी से कर सके। बहुधा देखा गया है कि जनता में किसी को कोई शिकायत हो तो वह उसके खिलाफ कोर्ट में जाये ग्रीर वहां शिकायत करे श्रोर फिर उसमें यह हो जाता है कि छतने का स्टैम्प हो, फलां कागज़ हो इत्यादि । गरीब क्रादमियों के पस स्टंम्प के लिए पैसे नहीं होते हैं । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसमें यह श्रा जाना चाहिए कि उसमें स्टंम्प की ग्रावइयकता नहीं पड़ेंगी, कम्प्लेन्ट सीषी ह्रौर सरल भाषा में की जा सकती है। मेरी प्रार्थंना है मंत्री महोदय दसको स्वीकार फरने की बृपा करें ।

धी कि० प्र० मंखल : सभाषति जी, मेरे पूर्ष वक्ता ने मेरे कार्य की हल्का कर दिया है।

मेरा संघोषन इस प्रकार है :
Page 9,-
after line 10, insert-'Provided that no stamp or fee of any type shall be charged for filing any complaint".

प्राज गरीब श्रादमी को क्याय नहीं मिलता है । भ्रदालत का हुख भ्रमीर भ्रादमियों के पक्ष में होता है । इसलिये में चाहता हूं कि क्म से कम लोकपाल और ल लोकायुक्त के इंस्टीट्यू्शन को घ्रौर श्रदालतों की तरह नहीं बनाना चाहिये। इसीलिये स्पेसिफ़कली हम चाहते हैं कि कोई स्टाम्प या किसी किस्म की फीस न लगे। माननीय त्यागी जी ने भी यही बात कही है, में भी यही कहना चाहता हूं, श्रोर क्राशा है कि मंत्री जी इस को भी मान लेंगे।

शी विध्या चरण शूक्ल : 【समापति जी, जहां तक माननीय शिव चन्द्र झा का संशोघन हैं वह चाहते हैं कि गुमनाम तरह से जो शिकायत भ्भाये उस को भी लोकभाल मन्जूर करे 1 इस विधेयक में जो हम प्राविषान कर रहे हैं उस में एफफीडेविट लगायेगा जो शिकायत करना चाहता है । क्यों कि बिना इस के यदि कोई कमप्लेन्ट करेगा तो काफी काम बढ़ जायेगा जिस को लोक,पाल प्रौर लोकायुक्त नहीं कर दायेंगे । इतलिये ऐफीडेविट लगाना जहरी है । श्रौर जब ऐफ़ीडेविट की बात श्रा गयी तो फिर गुमनाम रिकायत मन्ज़र करने का कोई प्रशन ही नहीं उठता । फिर मी एक प्राविषान है इस बिल में जिस की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, पोर वह यह है कि लोकपाल को इस बात का श्रषिकार दिया ुुग्रा है कि वह स्वयं हो कर बिना किसी शिकायत्त के भी किसी मामले की जांच पड़ताल कर सकते हैं। इस के लिये उन को कोई शिकायत की प्रावश्य: कता नहीं है 1 बिना शिकायत के मपर उन को संतोष हो जाये कि जांच करनी है:
[श्री विद्धाचरण शुक्ल]
तो वह जांच कर सकते हैं । ग्रोर इस तरह की व्यवस्था होने के कारण जो चीज माननीय सदस्य के मन में है fि लोकपाल को प्रधिकार .होना चाहिए, वह उन के श्रधिकार में श्रा जाता है, ग्रौर जब चाहे लोकपाल स्वेच्च्या से किसी भी मामले की जांच पड़ताल ख्युद कर सकते हैं चाहे ऐेफीडे विट हो या न हो, कोई गुमनाम $q$ त्र हो या न हो, जब चाहेगा भ्रपने श्रधिकार का उपयोग करके इस तरह की कार्यवाही कर सकते हैं।

जहां तक माननीय मंडल, माननीय रयागी ग्रोर माननीव श्री निवाप़ मिश्र जी के संशोषनों का सवाल है, मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कही हैं वह काफी ठीक बात है कि यदि कोई ¥ादमी जेल से या दूसरी जगह से पश्र भेजे तो उस में इस तरह की कार्यवाही करना स्टाम्प लगाना मुहिकल होगा, श्रोर हो सकता है कि मपनी तरफ से वह कार्यवाही करने में उस को कठिनाई हो। इसलिये मैं म्माप के संगोधनों को स्वीकार कर सकता हूं 1 पर जो संशोघन संशोधित रुप में माननीय मिश्र जी ने दिया है वह संशोषन ऐसा है जिस को में स्वीकार कर सकना हूं । इसलिये माननीय श्रीनिवास मिश्र जी का जो 54 नम्बर का संशोघन है उस को में स्तीकार करुंगा (व्यवषान) हम ने इस को बलेस किया था, लेकिन ग्रब श्रा१ इंस्टीट्यू शन शब्द वाहते हैं । माननोय मिश्रा जी के मंशोधन संख्या 52,53 के बारे में में .्राप को श्रमी बताऊंगा ।

संझोधित फार्म में जो संशोधन माननीय कमश्रा जी ने पेश किया है वह संशोधित कार्म मुझे मन्जूर है । उस में वही चीज़ है जो माननीय उयागी जी श्रोर माननीय मंडल जी चाहते हैं। ग्रोर मै उम्मीद करता हूं कि चूंकि माननीय श्रीनिवास मिश्रा जी का संशोधन स्त्रीकार कर लिया है इसलिये दोनों सदस्यगण श्रपने भ्रपने संशोधन, जिनका पंक मतलब वही है, वापस ले लेंगे।

माननीय मिश्रा जी के जो 52 घौर भ्रोर 53 नम्बर के संघोघन हैं उस्त में वह चाहते हैं कि 'प्लेस' की जगह ‘इंस्टीट्यूशन' किया जाये ।

समापति जी, श्राप को याद होगा कि जबप्रवरं समिति में यह मामला चल रहा था तो काफी बातचीत इस पर हुई थी श्रोर प्रवर समिति में ही हम ने ‘रिसेष्टिकल' को बदल कर 'प्लेस' किया था। श्रोर भब किर माननीय सदस्य चाहते हैं $f$ कि '‘लेस' बदल कर ‘इंस्टीट्यूशन' किया जाये । मेटी प्रार्थना है कि 'प्लेस' में इइंस्टीट्पूचन' खामिल है । 'प्लेस' में ऐसा नहीं है कि 'इंस्टीट्यूश्रन' ऐक्सकलूडड है । मोर चूंकि प्लेस बाड़ड घब्द है, उस में ये सब चीजें भाती हैं, ग्रोर जो माननीय सदस्य का मतलब है वह इस में शामिल है । इसलिये में चाहूंगा कि संशोषन संख्या 52 भोर 53 को वापस ले लिया जाय ।

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: I withdraw my amendment 17.

SHRI SRINIBAS MISRA: Except amendment 54 I would like to withdraw my other amendments.

SHRI B. P. MANDAL: Sir, I withdraw my amendment 132.

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Sir I withdraw my amendment No. 188.
Amendments Nos. 17, 52, 53, $132 \& 188$ were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is: Page 9, line 10, add at the end"and the Lokpal or Lokayukta as the case may be, may, if satisfled that it is necessary so to do, treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of sub-section (2)." (54). The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The question is: "That clause 9, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted. Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clause 10-(Procedure in respect of investigations).

SHRI B. P. MANDAL: I beg to move:

Page 9,-
after line 27, insert-
"Provided that no legal practitioner shall be allowed to appear on behalf of any party in course of such investigation." (133).
SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move:

Page 9,-
omit lines 14 to 18 ( 150 ).
Page 9, line 20,
for "offer his comments on such complaint or statement" substitute "explain his action." (151).

Page 9, line 27,-
for "during or after the investigation" substitute "or during the investigation." (152).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: beg to move:

Page 10, line 9,-
omit "and the public servant concerned." (189).

श्रो बि० प्र० मंडल : सभापति जी, मेरा मंशोधन है कि:
"Provided that no legal practitioner shall be allowed to appear on behalf of any party in course of such investigation."

नं. चाहता हूं कि लीगल प्रैक्टीशनर न रहे क्योंकि उसके बारे में गांधी जी ने My Experiment with Truth.
में लिखा है ग्रोर मुझे भी कुछ दिन मंजिस्ट्रेट 1905 (ai) LS- 17.

रहने का मौका मिला है ओर में जानता हूं कि हर दम यह कहना कि लीगल प्रैक्टीशनर की जरूरत है ऐसी बात नहीं है । इसलिए में कहूंगा कि लोकपाल ग्रीर लोकायुक्त को वकीलों, ऐडवोकेट लोगों के हाय से झ्रलग रखना चाहिए । नहीं तो झंझट होगा श्रोर लेंथी प्रोसेस होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि लीगल प्रैक्टीशनर रहे ।

ध्रो रामाबतार जासत्रो : सभापति जी, मेरे तीन संशोधन हैं । पहला संशोधन यह है कि पंक्ति 14 से 18 तक को हटा दिया जाय क्योंक उसकी कोई श्रावश्यकता नहीं है। उसमें यह बात कही गयी है कि कोई कम्पलेन्ट करे तो उसकी कोपी या श्रगर खुद लोकपाल या लोकायुक्त कोई इंवेस्टीगेशन करे नो उसकी ग्राउन्ड वह सम्बन्धित कर्मचारी को ग्रोर कम्पीटेंट श्रथोरिटी को भेजे। इसकी कोई़ जरूरत नहीं है ।

क्लाज़ (वी) में मेरा संशोधन इस प्रकार है :
"offer his comments on such complaint or statement."
मेरा कहना है कि इस को हटा कर वहां कहा जाय कि सिर्फ श्राप श्रपने ऐक्शन को एक्सप्लेन कीजिये । उन को यह मौका क्यों दिया जाय कि श्राप एक्सप्लेन कीजिये। जब चार्ज है तो लोकपाल का कर्तंव्य होना चाहिए कि उन से कहे कि ग्राप के ऊगर यह चार्ज है इस के बारे में श्राप को क्यां सफ़ाई देनी है वह् दीजिय ।

श्राखिरी संशोधन यह् है कि :
"during or after the investigation." श्रगर कोई इनक्वायरी हो रही है नो यह बात ठीक है कि इनक्वायरी के समय में जो गवाहृ है उसका नाम या श्रगर किसी के ऊपर कोई चार्ज है उसका नाम नहीं बतलाना चाहिए
[शी रंःावतार जास्ती] जनता को उस के पहलने स्रौर इनक्वायरी के समय में । लेकिन बाद में बतलांने में क्या दिक्कत है मेरी समझ में नहीं ग्राता।

श्रगर किसी ने गलती की है, भ्रष्टाचार किया है उस पर कोई श्रारोप है तो जब फैसला हो जाय तब बतलाने में क्या भापत्ति है। इसको बतलाना चाहिए ताकि जनता समझ जाय कि फलाने श्रफसर या फलाने श्रादमी ने डतना बड़ा भ्रष्टाचार किया ।

उसी तरीके से किस ने ऐेसा काम किया ग्रोर किस के कहने से किया जो गवाहु है उसका नाम भी बतलाया जाना चाहएिए ताकि जनता को यह भी मालूम हो कि हमारे जनतन्व में ऐसे जागरूक लोग हैं जो श्रगर कोई श्रफसर या मिनिस्टर या ग्रोर कोई गलत काम करता है, श्रष्टाचार के श्रभियोग में पकड़ा गया है उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। यह डीक है कि एनक्वायरी के बीच में ग्राप उस का नाम न बतलाये लेकिन बाद में इस तरह के काम करने वालों प्रोर गड़बड़ करने वालों का नाम जरूर बतलाना चाहिए।

मेरे ये तीन संशोधन हैं ग्रोर में समझता हूं कि मंत्री महोदय उन को स्वीकार करेंगे।

शी भ्रोम प्रकाश त्यागी : सभार्यति महोदय, इस विधेगक के क्लाज 10 में श्राया है कि :

In any case where the Lokpal or Lokayukta decides not to entertain a complaint or to discontinue any investigation in respect of a complaint he shall record his reasons thereof and communicate the same to the complainant and the public servant concerned.

मेरा इसमें ग्राज्जेकशन यह है कि किसी ने शिकायत की किसी गवर्न मेन्ट सवेंट के खिलाफ पौर वह उसको ठीक मानता है कि गड़बड़ हुई है, लेकिन लोकपाल या लोकायुक्त ने उसमें

कोई दम नहीं देखा या शिकायत गलन साबित हुई तो उसको गवर्नमेंट मवेंट के गाम क्यों भेंजा जाय। उस को कम्प्जेनेन्ट्ट के पास भेजा जाय गहु ठीक है लेकिन पब्लिक: सवेंट के पास जिस के खिलाफ शिकायत को गई हु. भेज देने के ग्रर्थ यह् होंगे कि कोई भी भ्रांदमी किसी श्रफसर के मम्बन्ध में शिकायत करने का माहस नहीं करेगा। हो सकता है कि उस ने ईमानदारी के साथ शिकायत की हो लेकिन वह् बात लोकपाल ग्रौर लोकायक्त की समझन में न श्राई हो। ऐेसो स्थिति में शिकायत करने वाले के पास उम कों भेज देना ठीक है मगर पब्लिक सर्वेंट के भास भेजने की बात को में ठीक नहीं समझता । चूंकि शिकायत करने के बाद श्रादमी के सामने कठिनाई श्रा सकती है क्योंकि जिस भ्रफसर के ग्रन्डर में वह्ट काम करता है उसके बिलाफ शिकायत गलत साबित होने पर उसको नोकरी से भी हाथ घोना पड़ सकता हैं इस लिए भय के कारण कोई श्रफसर की शिकाय: नहीं करेगा। इसलिए इस वाक्य को हटा देना चाहिए कि पबिलक मवेंट के पास भेज दिया जायग ।

भी विद्या चरण श्रुक्ल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री मंडल चाहते हैं कि इस में वकीलों को न जाने दिया जाय । इसके बारे में प्रवर समितित में काफी चर्चा हो चुकी है। ज्यादातर सदस्यों का यही ख्याल थr जो श्री मंडल का है कि वकीलों को जाने से बहुत सी कडिनाइयां डस सम्बन्ब में पैदा हो सकती हैं। इसी लिये हम लोगों ने इस क्लाज में नय किया कि जो लोकपाल या लोकायुक्त हैं वह स्वयं श्रपनी रीति श्रयवा प्रोसीजर को तय करेंगे। उन्हें इस बात का अ्रधिकार रहेगा कि वह चाहें तो वकीलों का श्राना रोक सकते हैं । ऐेंेे भी मामल ख्रा सकते हैं जिनमें बहृत गरीब भ्रीर ऐसे लोग जो सरकारी नोकर हैं जो लोकायुक्त भार लोकपाल के सामने जाकर भ्रपनी fिकायके

को स्वयं नहीं रख सकते ठीक से ग्रौर उनको किसी सफाई देने वाले की ग्रावश्यकता हो सकती है, ऐसी स्थिति में लोकपाल श्रौर लोकायुक्त के पास इस बात का ग्रधिकार रहेगा कि ग्रगर किसी एश्रोप्रिएट केस में वह चाहे तो उनको ग्राने दे । पर इसमें यह साफ बात है कि उनको इस बात का ग्रधिकार भी दिया गया है कि जब वह ग्रपने रूल्स ग्रौर प्रोसीजर बनायेंगे तब चाहें तो वकीलों का ग्राना बन्द कर सकते हैं। उनको इस बात का पूर्ण अधिकार रहेगा। इसलिये श्री मंडल के संशोधन का जो उद्देक्य है वह इस धारा से पूर्ण हो जाता है । मैं उम्मीद करता हूं कि ड़स बात को देखते हुए. वह्ह ग्रपने संशोध्रन पर जोर नहीं देंगे ।

जहां तक श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन का सवाल है, मैं बतलाना चाहता हूं कि लोकपाल घ्रौर लोकायुक्त की जो कार्वाई होती है वह श्रन्तिम कार्रवाई नहीं है । प्राइमा फेसी केस हैं या नहीं इसको जानने की बात है । उनका जो ग्रमेंडमेंट है उसमें उम्होंने कहा है कि लाइन 14 मे 20 तक हंटा दिया जायं । इसका मतलब होगा कि ग्रगर हम किसी भी सरकारी कर्मचारी से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो जो कापी ग्राफ दि कम्प्लेन्ट है वह नहीं मिलेगी। ह्मारी जो रीति है, जसं बिल में रेखा गया है, उसके झ्रन्तर्गत पहले कापी देनी होगी जो ग्रारोप लगाये गये हैं उनकी ग्रोर उसके बाद वह जवाव देगा। यदि पहले ह्म एक्सप्लेनेशन मांगें ग्रीर कापी बाद में मिले तो एक्सप्लेनेशन किस बात का मिलेगा ? झ्रगर इस संघोधन को मंजूर कर लिया जायेगा तो जो प्राकृतिक न्याय की प्रक्भिया है उस में बाधा पड़ेगी ।

तीसरा मंशोधन है कि जो झ्यादमी शिकायत करे उसका नाम भी मामने श्राना चाहिये ग्रोर जिसके खिलाफ, शिकायत करे उसका नाम भी श्राना चाहिये जैसा में कह रहा था जब केस के ऊपर निर्णय श्रा जाय तब उस व्यक्ति का नाम श्रा जाय तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन

जब तक निर्णय न हो झ्रीर निर्णय के बिना ही उसका नाम फैला दिया जाय ग्रौर कहा जाय कि इस के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, यह कार्रत्वाई हो रही है,वह कारवाई हो रहीं है, उसकी बहुत बदनामी हो जाय ग्रौर बाद में वह निर्दोष सिद्ध हो जाय तो बदनामी के कारण उसको कष्ट सह्ना पड़ेगा वह तो हो ही जायेगा ।

धी रामाबतार शास्र्रो: ‘ड्यूर्रिंग श्रार् छ़ाफ.टर दि इंवेस्टिगेशन ।'

श्री विद्धा चरण झुषल : मैं बतला रहा हूं । ग्राफटर ड़न्वेस्टिगेशन भी चार्ज सिद्ध नहीं हुग्रा तो लोकपाल म्रौर लोकायुक्त जो काम करेंगे, जो उनकी फाइंडिंग होगी उसके बाद डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी के लिये केस जायेगा क्योंकि सजा देने का ग्रध्रिकार लोकपाल ग्रौर लोकायुक्त को तो नहीं है । वह तो केवल प्राडमा फेसी केन है या नहीं यह देखते हैं i वह् ऐप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल ऐकशन के लिये भेजेंगे । डिपार्टमेंटल ऐक्शन की कार्रवाई पूरी हो जायेगी, उस के बाद सझा मिलेगी। लोकपाल ग्रौर लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद ग्रपराँध मिद्ध नहीं हुग्मा, पर श्रपराध किया ह इसकी संभावनाव्यक्त होती है डसलिये वहां भेजते हैं। वह यह कह सकते हैं कि इसका कोई ग्रपराध रसद्ध नहीं हुग्रा है इसलिये इस पर कोई कार्रवाई न की जाये । पर कई केसेज ऐसे हो सकने हैं जिन पर कह सकते हैं कि इस पर झ्रपगाध्र करने का प्राइमा फेमी ःेके है डस लिये इमे डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी के लिये दिया जाये । जिस डिपार्टमेंट से सम्बन्धित होगा वहां जाकर जो डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी का प्रोसेस है वह फालो होगा। वहां $\mathrm{T}^{-}$उसका ग्रपराध सिद्ध ह्रेगा या ग्रसिद्ध होगा। इस लिये पहले से नाम बतला देना टीक नहीं होगा। यर्द्यं; कई एसे मामले हो सकते हैं जिन के बारे में ग्राम जनता की काफी रुचि है, काफी कोवूहल है 1 ऐसे मामलों को छिपा कर रखान
(श्रों विद्याचरण श्रुक्स)
किसी स्भी स्टेज पर उर्उत नहीं होगा । इस लिये हम लोगों ने इस बिल में यह प्रावधान किया है कि ऐसे केसेज पब्लिक हिश्रारंग के लिये हो सकते हैं। वह इन कैमेरा हिर्भररिग के लिये जायें यह झ्रावश्यक नहीं है । इस तरह के निदेश लोकायुक्त घ्रोर लोकपाल को दिये गये हैं कि जो मामले याँ,मुकदमे ऐसें हैं जिनमें वह्ट ममझते हैं कि श्राम जनता को काफी रुच या कौतूहल है, जिनकी इम्पार्टसें इतनी है, उन्हें ग्रार्मजजनता किय़ सामने खोल कर रबना चाहिये शुरू से 1 लोकपाल को यधिकार है कि वह ऐसा कर सकते हैं । इस लिये में नहीं समझता कि हमें ऐसा प्रावधान करना चाहिये कि हम सब केसेज खोल दें जिनमें ग्राधे लोग बेचारे "श्रन्त में निद्दोष सिद्ध हों। इसलिये पहले से नाम श्रा जाय हससे न्याय पूरा होने की स्थिति नहीं होगी है।

में माननीय सदस्यों से निवदन कहूंगा कि उन्होंने जो संशोध्रन मूव किये हैं उन्हें वह हटा लें म्रंर इस क्लाज -े फ़ंये का तैसा पास कर दें

ध्रो प्रोम प्रकाइा त्यागी : मेरी बात का जवाब नहीं दिया गया। गवर्नमेंट सवेट्म के पास कम्प्लेंट के भेजने का क्या तात्पर्य है ? किसी की शिकायन को लोकपाल ने ठीक नहीं समझां। तो उसकोंकम्लनेंटन के पास भंज देंगे साथ ही जिसकी शिकायत है उसके पास भेज देंगे, इस का क्या मतलब है ?

भो विद्धा चरण शुष्ल : इसकी प्रकिया जो है उसको लोकपाल श्रौर लोकायुक्त स्वयं नय करेंगे कि उसमें क्या करना है ।

श्री श्रोम प्रकाश त्यागी : फिर गवर्नमेंट सबेंट के पास भेजने का क्या मतलब है ? तब कोई शिकायत ही नहीं करेगा ।

श्री विद्या चरण शु कल : यदि किसी के बिलाफ भिकायत है और्र उसका हम एक्स-

प्लनेश्न चाहें तो उसके पास शिकायत का प्रारूप तो भेजना ही पड़ेगा ।

धी श्रोम प्रकाश त्यागी : इस तरह से नहीं । घ्रगर लोकपाल उसको ठीक नहीं समझ्शता है तो वह कम्प्लेंट को देने ही बापस कर दें, जिसके खिलाफ शिकायत है उसके पास क्यों भिजा जायेगा ?

16 hrs .
भी विष्षा चरण शुषल : ग्रापकी श्रमेंडमेंट का नम्बर क्या है ?

धी प्रोम प्रकाश त्यागी : मेरी एमेंडमेंट है पेज 10 , लाइन 9 पर ....

भी विद्या चरण शुक्ल : जब भी लोकपाल किसी के खिलाफ इनक्वायरी करना चाहता है तो उस कम्प्लेंट की कापी को उस सरकारी पघिकारी के पास वह भेजता है श्रौर उससे कहता है कि वह उसके बारे में जो कहना चाहे कहे । सरकारी अ्रधिकारी को यह पत्ता रहता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात हो रही है । उसको पता रहता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला . . .

भी श्रोम प्रकाश ल्यागो : ऐसा नहीं है। पेज 10 पर म्रापने कहा है :
"In any case where the Lokpal or a Lokayukta decides not to entertain a complaint or to discontinue any investigation in respect of a complaint, he shall record his reasons therefor and communicate the same to the complainant and the public servant concerned."

भी विद्या चरण शुक्ल : में ममझ्ञ गया हूं। प्रार्कृतिक न्याय के लिये यद्ट बहुतुत जस्री है, इसलिए ड़स ग्रमेंडमेंट को में मंजूर नहीं कर सकता हूं ।

भी प्रोम प्रकाश ${ }^{\Gamma}$ त्यागो : कोई रोजन भी तो दें।

श्री विद्धा चरम शूक्ल : मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो प्रक्रिया हमने यहां रबी है, उसमें एक स्वाभाविक प्रौर. एक प्राकृतिक न्याय देने की बात हमने कही है । इस प्रक्रिया में जरा भी फेरबदल किया जाएगा तो न्यायनहीं मिलेगा ।

भी। जोन "पफकाओंत्र त्याती: सिकायत करने वाला श्राफिसरं के बिलाफ शिकायत करेा लेकिन लोक्षाल ने श्रार उस शिकायत को ठीक नहीं समक्षाूतो फिर उस मामले को बबल करो। माप उस बक्मलेंट को अफसर के पास क्यों मेजते हैं । कहां तो श्राप वह कह रहेहैं कि बद्तामी न हो जाए लेकित किर पाप उस किकायत को अ्रफसर के पास मेज देंगे। इससे उसकी नोकरी घतरे में हो बाएगी। उसके पास श्राप क्यों किर उस नितापत को मेज रदे हैं। बकुछ, सक्य तो प्रापका होगा इसको रखने में ? कंसन्ह पन्लिक सबैट के पास आ्राप किर इसको क्यों मेज रदेंदें ?

SHRI B. P. MANDAL: I beg to leave of the House to withdraw my amendment.
Amendment No. 133 was, by leave withdrawn.
MR. CHAIRMAN: I shall now put the other amendments to clause 10 to vote.

Amendments Nos. 150, 151, 152, 189 were put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That clause 10 stand and part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 10 was added to the Bill.
Clause 11- (Evidence.)
SHRI SRINIBAS MISRA: I beg to move:

Page 11, line 9,-after "shall" in-sert-cunless the investigating authority after examining the
question specifically so directs," (55).

Page 11, line 25, for 'binding and conclusive' substitute 'prima facie evidence of such nature'. (56)

Page 11, omit lines 26 to 29. (57). SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 11, line9, for 'person' substitute 'Government employee'. (190).

SHRI SRINIBAS MISRA: Clause 11 speakes about the evidence to be taken by the Lokpal or Lokayukta. It rather aims very high that he will take evidence, untrammelled by all rules, and no person should claim any privilege to secrecy. But I do not understand how after sub-clause (4), the following sub-clause has been put, in, namely-
"No person shall be required or authorised by virtue of this Act to furnish any such information or answer any such question or produce so much of any document-
(a) as might prejudice the security or defence or ...."
-so far, that is understandable and intelligible but, what about the subclause (b) which follows, namely-
"(b) as might involve the disclosure of proceedings of the Cabinet of the Union Government or any Committee of that Cabinet or of the Cabinet of the Government of any Union territory or of the Executive Council constituted under the Delhi Administration Act, 1966, or of any Committee of such Cabinet or Executive Council....".

Somebody who is asked to give evidence can take shelter under this provision. If a Secretary certifies that this will come under either 5 (a) or 5 (b), that will be sonclusive. I suggest that after 'shall', we should add 'unless the investigating authority after examining the quetion epecially so direct'. All these matters should be
[Shri Srinibas Misra]
placed before the Lokayukta or Lokpal; he should look into it and then decide. If he specially directs, it must be produced. If not, it will not be produced.

As regards the last one, that it should be binding and conclusive, it cannot be so. It can. be rebutted. Once a certificate is given by a Secretary, it will only mean that on prima facie evidence it will come under 5(a) or 5 (b). But it is open to the other side to challege that it does not come under either of these.

शी घोम प्रक्काश त्याग़ी : सब क्लाज 5 में लिखा है "नो परसन शैल वी रिक्वायर्ड" । यानी किस भी ख्रादमी से़ इस झकार का डाकुमेंट नहीं मांगा जा सकेगा जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो या दूसरे देशों के साथ, मन्तर्रण्ट्रीय सम्बन्घ जो हैं, उनको प्रभावित करता हो ।

किसी भी गवनें मेंट सवेंट से इस प्रकार का रिकार्ड मांगा जाए जो हमारी डिफेस से सम्बन्ध रखता हो या हमारी कंबिनेट की ज़ो प्रोसीडेंग्ज हैं, उनको मांगा जाए तो मैं इस को आ्यनुचित समझता हूं। डसको नहीं मांगा जाना चाहिए। श्रगर मांगा जाता है तो श्रगर कोई भी व्यक्ति न दे तो ठीक है । लेकिन मान लो यहां कोई सी घ्याई ए का एंंट है, श्रमरीका का, रशिया का, चोन का या पाकिस्तान का एबेंट है श्रोर वह पकड़ा जाता है ग्रोर उसके पास कुछ इस प्रकार के सीक्ष्ट्स हैं जिन के प्राउट होने से पाकिस्तान, रशिया या घमारीका के सम्बन्धों में गड़बह़ होगी तो क्य श्राप उस एजंट से डाकुमेंट मांग सकेंगे या नहीं मांग सकॅंगे, यह में झ्राप से जानना चनहता हूं। में उदाहरण देता हूं । मान लो किसी जगह पर कम्युनल रायट हो जाता है द्योर मान लो कि उस कम्युनल रायट में फिसी विఖेष क्रा, मान लो मुसलयागों के साथ कोई बड़ा श्रत्याचार हो जाता है भ्रोर बह् किसी एजेंट के कारण होता है

ग्रौर हो सकता है कि वह ग्रादपी यह् कह दे कि इस डाकुमेंट के प्रकट होने से इसका प्रभाव हिन्दुस्तान म्रौर पाकिस्तान के सम्बन्धों पर जा कर पड़ेगा, तो क्या इस कारण से उस डाकुमेंट को ग्राउट करने की ड़जाजत नहीं दी जाएगी। मान लो चीन का कोई जंट पकड़ लिया जाए यौर वह कहता है कि जो डाकुमेंट है उसको मैंने दे दिया तो जो तुम्हारे स्नम्बन्ध बने हुए हैं वे बिगड़ जययंगे या श्रमरीका का श्रादमी पकड़ा जाता है मौर वह कहता है कि तुम्हारे सम्बन्ष घमरीका के साथ खराब हो जाएंगे, तो क्या इस कारण से म्राप उस डाकुमेंट को माउट करने की ग्राप इजाजत नहीं देंगे ? घगर सरकार न दे तो बात समझ में क्मती है बेकिन झापने तो लिखा है "नो परसन" इस्म में तो एजेंट भी श्रा जाएगा । घ्रब वह एजेंट झ्रापको वह कागज देगा या नही ? इस वास्ते मैंने सुझाव दिया है कि नो परसन की जगह गवर्नमेंट एम्प्लायी कर दें । श्रगर कोई एर्जेंट पक़ड़ा गया भ्रौर उसने यह प्ली लेली तो श्राप कुछ नहीं कर सकेंगे । यहां पर इस प्रकार के वकील हैं, एडवोकेट हैं, जो चोरों का, डाकुप्मों $\Gamma$ श्र्रार गद्वरों का भी साथ देते हैं। ग्राप उस श्रकस्था में इस का क्या एक्सप्लेनेशन देंगे । इस वास्ते नो परसन की जगह श्राप गवनंमेंट एम्प्लायी लिख दें ।

धी विद्या परण श्रुक्स : सिश्र जो ने श्रपने संश्रेधन में कहां है कि क्लाज 11 (5) (ए) का संशोधन किया जाए घ्योर एक एक्सैपशन किया जाए ताकि जो सरिटिकेट कोई सैक्रेटरी या गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, उसको वह ग्रोवर राइड कर सके श्रोर जो डाकुमेंट हम नहीं देना चाहते हैं उनको देने के लिए भी वाध्य किया जा सके। सवाल इतना ही पैदा है कि यदि कंबिनेट को फंकशन करना है तो कैबिनेट के डाकुमेंट या कँबिनेट प्रोसीडिंग्ज यदि इनको भी हमें देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो फिर

कंबिनेट सिस्टम जो है, उसको चलाये रखना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, कैबिनेट का जो हमारा काम चल रहा है, उसका चलना बिल्लुलं मुक्किल हो जाएगा। इसके ऊपर हमने काफी सोच विचार कियाएै । दूसरी बात यह है कि एम्ब्ब्ड्जमैन के जो विधियक बाहर बने हैं इसके सम्बन्ध में कानून बाहर बने हैं, उनकी तरफ भी हमने ध्यान दिया है। हमने देखा है कि जहां यह संस्थ ग्रच्छी नरह से कान कर रही हैं, उनके वहां भी यह प्रावधान हैं कि यदि सरकार द्वरा कोई कागज या सूचना प्रकट किये जाने पर जन-हित की हानि की ग्राशंका हो, तो सरकार के लिये उस कागज या मूचना को भेजना म्रावश्यक नहीं है प्रीर जब इस अ्राशय का सर्टिफिकेट सेक्रेटरी द्वारा दिया जाये, तो उसको मंजूर कर लिया जाये । इसलिये मैंनहीं समझता कि हम माननीय सदर्ग के संशोधन को मंजूर कर सकते हैं। अ्रणर ऐसे डाकुमेंट पेश कर दिये जायें, तो जो बाद में सबके सामने श्रा जायें, तो उनसे दूसरे देशों के साथ हमारे मैनीपूर्ण सम्बन्ध नष्ट हो सकते हैं आौर श्रागे चल कर बढ़ी कटिनाई पैदा हो सकती है ।

श्री त्यागी ने यहु संशोधन रखा है कि "पर्सन" की जगह "गवर्नमेंट इम्प्लाई" रख दिया जाये । हम जाहते हैं कि इस व्यवस्था को जहर वाडड रखा जाये, ताकि इसके अ्रन्तर्गंत न केवल सरकारी कर्मचारी, बल्कि हर एक व्यक्ति ग्रा सके। इसको रखने से लोकपाल ग्रौर लोकायुक्त को यह ग्रघिकार होगा कि वे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या न हो, बुला सकें भ्रोर इस बारे में कार्यवाही कर सके। "गवर्नेंटंट एम्प्लाई" शब्द रखने से पब्लिक सेक्टर के एम्प्लाईज, यूनिःन टेरीटरीज में म्यूनिसिपल कारपोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी के कमंचारी इसके ग्रन्तर्गत घामिल नहीं होंगे, के इस प्राविजन के परिधि से बिल्कुल ब्राहर हो जायेंगे । इसर्मत्ये "गत्रनमेंट एम्ल्लाई"

क्रा श्रोम प्रकाश त्यागी : मान" लीजिये किं"किसी कन्ट्री का कोई", एजेन्ट पकड़ा जाता है मौर वह इस व्यवस्था का लाभ उठा कर कहता है कि ग्रगर वह श्रमुक कागज या सूचना पेश करेगा, नो उम कन्ट्री के साथ. उदाहरण के लिये रशा के साथ, रिलेशन्ज खराब होंजायेंगे । मंनी महोदय का। इस बारे में क्या कहना है ?

भ्रो विक्षाचरण घुक्ल : उसके ऐसा कहने से कोई भ्रभाव नहीं होगा, जब तक कि सरकारी श्रघिकारी स्वयं इस श्षाशय का सर्टफिकेट न दे । किसी व्यक्ति के स्सट्िफेकेट देने या कहने से काम नहीं चलेगा। लोकपाल या लोकायुक्त के पास मंत्नि-मंडल के सचिव या सरकार के किसी म्रन्य सचिव की तरफ से "जो सर्टफिकेट दिया जायेगा, केवेल वही लागू होगा, किसी गी व्यक्ति का सटिफिकेट लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति कहत्त है कि ग्रमुक कागज या सूचना को प्रकट करने सेंहमारे मित्न देशों के साथ सम्बन्बों में नुकसान होया, तो वह सर्टटफिकेट लोकपाल या लोकायुक्त पर लागू नहीं होगा। इसलिये माननीय सदस्य ग्रपने संशोधन :को प्रेस न करें ।

MR. Chairman: Have Mr. Tyagi and Mr. Misra leave of the House to withdraw their amendments?
Amendments Nos. 55 to 57 and 190. were by leave withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is: "That clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 11 was added to the Bill.
Clause 12-(Reports of Lakpal and Lokayuktas.)
SHRI LOBO PRABHU: I move:
Page 12, line 22,-
for "President" substitute
"Speaker" (77).
[Shri Lobo Prabhu]
Page 12, line 30,-
for "President" substitute
"Speaker" (78).

## SHRI OM PRAKASH TYAGI: I

 move:Page 12, line 27,add at the end-

> "and the President shall cause it to be laid before the Parliament within three months."(192).

SHRI LOBO PRABHU: Sir, in these amendments and some others which have already been passed over, I have raised a fundamental issue whether the Lokpal will be a Commissioner for the Parliament or a Commissioner for the Government. There is a vital distinction of the Lokpal being under the President and being under the Speaker. If the Lokpal is under the President, according to the present constitutional practice, he is under the orders of the Government, the Prime Minister and of her Ministers concerned. He is by no means independent. The question is: when he differs from the Government, when he differs from the Prime Minister, and he functions through the President, has he a fair chance of presenting his case? Is the President likely to differ from the Prime Minister or the Minister concerned? The President has been unfortunately a rubber-stamp according to our constitutional practice. He is bound to take the advice of the Prime Minister. How can he then, when he gets these papers showing difference of opinion, between Lokpal and the Prime Minister, have his own difference of opinion? It means this: that if you interpose the President, any power to differ from the Government for the Lokpal, would be a redundant exercise serving no purpose. It is almost deceiving the people.

Not only is this a constitutional impasse. There is the fact that the President and the Government have not been able to take sufficient work,
sufficient use, from the authorities they have previously appointed to control corruption. I refer to the Grievance Commissioner and to the Vigilance Commissioner. I need not tell this House that this Grievance Commissioner, after existing for about threc years, was ultimately found to be useleas and was abolished. As far as the Vigilance Commisioner is concerned, the last report of the Home Ministry showed that while he began with a list of 6,000 complaints in the first year, last year those complaints were reduced to only 1,000 . The people had so quickly lost their faith in this Vigilance Commissioner as they had lost faith in the Grievance Commissioner. The only reason for this is that he was part of the Government: he was a limb of the very persons whom he was supposed to check. We have a theory here that the Government can do no wrong: the divine right that the King can do no wrong. That theory extends to every Government servant!

MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI LOBO PRABHU: I am concluding. This is a very vital issue.
MR. CHAIRMAN: Please speak on your amendment only.

SHRI LOBO PRABHU: This is my amendment. My amendment, therefore, is that for the word "President" wherever it occurs and particularly in this section, substitute the word "Speaker." The Speaker is the representative of the House. The Speaker is the competent authority to appoint many officials; he has his Secretary and all the other staff. I cannot see why the Lokpal should not be under the Speaker.

I would like the Minister to carefully consider this. You must give confidence to the people. You must not give them the feeling that their complaints are just being addressed to a blank wall and that they are only indulging in an exercise of futility. If you make this change, while it may appear to be a big change, you will be
giving the Bill some form of eredibility as far as the public is concerned.

श्री घोम प्रकाझ त्यागो : सभापति महोदय, सब-क्लोज (6) में कहा गया है कि लोकपाल मौर लोकायुक्त ग्रपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूंदि कि हमारे संविधान के श्रनुसार लोक सभा को सर्वोज्च सत्ता माना गया है। इस लिए देश मर के प्रत्येक सरकारी कार्य का विवरण लोक समा के सामने श्राना ही चाहिए, चाहे वह किसी के ध्र्ग श्राये, प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट या स्पीकर के :गुर श्राये, जिससे देश की सिथिति का पूरा चित्र लोक सभा के सामने क्रा सके । घोर एक व्यवस्था कि लोकपाल किस ढंग से कार्य कर रहे हैं वह उस के सामने भा सके। हसलिए जो प्रेसिड्डेट को रिपोर्ट श्राए तो मेरा झ्रमेंडमेंट यह है कि
> "and the President shall cause it to be laid before Parliament within three months".

तीन महीने के घन्दर प्रेसीडेंट साहब को जो वाषिक रिपोर्ट मिली है वहन, पारियामेंट के सामने उपस्थित कर देनी चाहिये। यह् मेरा सुझाव है। घगर श्राप इत को नहीं रखते हैं श्रौर वह रिपोर्ट केवल प्रेसीडेंट तक ही रह जाती है तो मैं समझता हूं कि संविधान की भावना पर मी पालियामेंट की लोक सक्ता पर भी भाषात ग्राता है। इसलिए यह शब्द जोड़ दिए जायं , यह् मेरी प्रार्यना है।

श्री विध्धाचर्स शुक्ल : श्रध्यक्ष महोदय, श्रीमान लोबोप्रभू ने यह कहा है कि जो लोकपाल की रिपोर्ट श्राए उसे रपीकर के पास भेजना चाहिए, प्रेसीडेंट के पास नहीं । में उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोकपाल की रिपोर्ट श्राएगी उसे गवर्नमैंट के एक्सप्लेनेशान के साथ यहां पेशा करना पड़े गा श्रौर गवर्नर्न मेंट के ऊपर इस कानून के प्रन्तर्गत एक बन्बन लग गया है कि उन्हें वार्षिक रूप से इस रिपोर्ट को सदन के सामने रखना श्रावरयक है। इस

लिए रिपोर्ट स्पीकर के वास यदि क्राए ग्रोर स्पीकर हाउस के सामने रख दे, उस में गवर्नमैंट का एक्सप्लेनेशन न रहे तो माननीय सदन को यह बात ठीक समझ में नहीं ग्राएगी कि यदि उस रिपोर्ट में कोई ऐसी बातें हैं जिन को गवर्नमेंट ने मंजूर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो उस का एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम जो गवर्नमेंट को देना है वह तब तक नहीं ग्रा सकता जब तक कि प्रेसीडेंट उस रिपोर्ट को न ले श्रौर गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेट्री मेमोरेंडम ले कर उस को सदन के सामने नरखे। वा् चीज सदन के सामने श्राएगी क्योंकि इस का प्रावघान इस विषेयक में किया गया है। दूसरी बात यक है कि जैसे कम्प्र्रोलर ऐंड श्राडीटर जनरल की रिपोर्ट है वह भी प्रेसीट्डेंट को जाती है, वह भी स्पीकर के पास नहीं श्राती, प्रेसीहेंग के पास ग्राती है म्रौर गवर्नमेंट उस में जो ब्योरा देती है जो म्रपना एक्सप्लेनेशन देती है उस के साथ वह सदन के सामने ग्राती. है। इसलिए जो प्रक्रिया बनी है कि जब इस माननीय सदन के सामने वह रिपोर्ट श्राए तो उसमें गवर्नमेंट का भी पूरा व्योरा एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ रहना चाहिये वही प्रक्रिया ज्यादा श्रच्छी होगी कि बजाय स्पीकर के प्रेसीडेंट के पाव वह रिपोर्ट श्राए श्रोर वहां से हर साल जैसे श्रौर रिपोर्ट्स को यहां रखना वड़ता है वैसे ही गवर्नमेंट के मेमोरेंडम के साथ यह रिपोर्ट भी यहां श्राए। इसलिए जो प्रक्रिया ? रखी गई है वह्टी रखनी चाहिए श्रोर स्पीकर के पास रखने में उस में देर होगी। स्पीकर को फिर सरकार के पास भेजना पड़ेगा ग्रौर सरकार फिर देखभाल करेगी ग्रौर तब भ्रपनी रिपोर्ट उस पर यहां पेशा करेगी, तब माननीय सदस्य उस पर सोच विचार कर सकेंगे । शुर्ह से दोनों चीजें एक साथ ग्रा जायेंगी तो उस रिपोर्ट परविचार करने में सुविधा होगी ।

उसी तरह से माननीय त्यागी जी ने जो श्रपना श्रमेंडमेंट दिया है उसमें वह चाहते हैं कि तीन महीने के श्रन्दर इस रिपोर्ट को
[श्री श्रोम प्रकाश त्यागी]
सदन के सामने पेश किया जाय । में उन का ध्यान ग्रार्कषित करना चाहता हूं कि पैरा 7 के श्रन्तर्गत वार्ाषक रूप से इस सदन के सामने इस रिपोर्ट को सरकार को पेश करना पड़ेगा । उसमें किसी तरह का बीच बचाव नहीं है कि सरकार देर कर सके। ग्रगर देर होने की संभावना होती तो मैं ग्राप का ग्रमेंडमैंट जरूर स्वीकार कर लेता । लेकिन क्यों कि हमने खुद इस का प्रावधान किया है कि वार्षक रूप से यह रिपोर्ट सदन के सामने ग्राए जैसे यू० पी० एस० सी० की या ग्राडीटर जनरल की ग्राती है ऐसे ही यह भी ग्राए इसलिए उसे स्वीकार करने की ग्रावश्यकता नहीं है । यह कहना कि तीन महीने के ग्रन्दर रिपोर्ट ग्रानी चाहिए, उस से कोई लाभ नहीं है क्योंक इस में प्रावधान है कि जैसे वांषिक बजट श्राता है या यू० पी० एस० सी० की रिपोर्ट श्राती है, ग्राडीटर जनरल की रपांर्ट श्रात, है ऐसे ही इस को भी सदन के सामने रखा जाय । उस को जोड़ने से कोई विशेष फायदा नहीं है। इस लिए में माननीय सदस्यों से प्रार्थना करुगा• कि वह ग्रपने संशोधनों को वापस ले लें।

MR. CHAIRMAN: Shall I put all the amendments to the vote of the House?

SHRI LOBO PRABHU: Sir, I may be permitted to press my amendments, because they are very important and I believe in them.

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment Nos. 77 and 78 to the vote of the House.

Amendments Nos. 77 and 78 were put and negatived.

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Sir, 1 want to withdraw my amendment.

MR. CHAIRMAN: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment?

SOME HON. MBMMBIERS: Yes.

## Amendment No. 192 was, by leave, withdrawn

MR. CHAIRMAN: I will now put clause 12 to the vote of the House.

श्रो प्रों कररलाल बे रबा (कोटा) : बंयरमंन महोदय, यह कैसे पंस कर रहें हैं, सदन में कोरम नहों है ।
Mif. CHAIRMAN: The bell is being rung ... Now there is quorum. The question is:
"That clause 12 stand part of the Bill.

The motion was adopted.
Clause 12 was added to the Bill.
Clauses 13 to 15 were added to the Bill.

## Clanse 16-(Protection.)

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, I move:

Page 14, lines 28 and 29,-
for "or any member of their staff and employees"
substitute-
"or against any officer, employce, agency or person referred to in section 13" (11)

This amendment has been found necessary to give protection to the agencies or persons referred to in clause 13 in respect of anything which is done in good faith. It is slight amendment which is being moved so that they are protected for any action taken by them in good faith.

MR. CHAIRMAN: The question is: Page 14, lines 28 and 29,-
for "or any member of their staff and employees"
substitute-
"or against any officer, employee, agency or person referred to in section 13" (11)

The motion was adopted.
$\because M R$. CHAIRMAN: The question is:
> "That clause 16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clause 17 was added to the Bill
Clause' 18- (Power to exclude complaints against certain classes of PubIic Servants.)

SHRI SRINIBAS MISRA: I do not want to move my amendment. I will only commend to the Government to be consistent and logical. Here, it says, "a minimum monthly salary (exclusive of allowances) of one thousand rupees or more". What is the minimum? One thousand rupees or more? You say, it will be one thousand rupees or more. It is illogical. If you say, a minimum of one thousand rupees, it is all right. Why say a minimum of one thousand rupees or more? To make it logical, I suggest, it should be a monthly salary of one thousand rupees or more. To add the word "minimum" will not add to the dignity of the drafting or will not give them any more facility or make it more comprehensive.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Actually, it is kept at the discretion of the Lokpal. It is done on his recommendation. This is necessary to ensure proper and efficient functioning of the institution. Otherwise, so many cases may come to the Lokpal and Lokayuktas and their proper functioning will become impossible. So, I would request the hon. Fiember, in view of the practical difficulties that we have, not to press that.

SHRI SRINIBAS MISRA: You say, a minimum monthly salary of one thousand rupees or more. Is minimum one thousand rupees or more? Minimum must be a flxed sum. You say, minimum of one thousond rupees or more, that is, two thousand rupees may be minimum
or even five thousand rupees may be minimum. Why do you say "minimum"? Why don't you say one thousand rupees or more?
SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Almost all the posts in Government do not carry a fixed salary. They have a scale of pay having a minimum and a maximum for a span of years. Therefore, it will be necessary to specify the posts which carry a minimum; more cannot be added or excluded by the notification. The allowances attached to the post may vary. So, to have a uniform treatment, it will be necessary to go by the salary attached to the post without allowances at arriving the figure of one thousand rupees.
SRI SRINIBAS MISRA: He is defending something ińdefensible. You say a minimum of one thousand rupees or more. You may say, a minimum of one thousand rupees. What is the meaning of "more"? Does it carry any meaning?

शी घटर्लविहारी बान्कपेयी (घलरामपुर): सभार्पति जी, शायद मतलब यह है कि त़नखाह कम से कम एक हजार होनी चांहिए, ज्यादा भी हो सकती है, में भाषा के बारे में कुछ्व नहीं कह सकता ; लेकिन सन्ज्शा ठीक है 1
SHRI C. K. BHATTACHARYYA: (Raiganj): The sentence involves self-contradiction. Either the word "minimum" should be removed or the word "more" should be removed.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We consulted our legal draftsman. There is no contradiction in it. I would say, it should be accepted as it is. We were ourselves concerned when this amendment was received by us. We got it examined.

MR. CHAIRMAN: Now, I put clause 18 to the vote of the House.
The question is:
"Clause 18 stand part of the Bill." The motion was adopted.
Clause 18 was added to the Bill.
[Mr. Chairman]
Clauses 19 to 22 were added to the Bill.

The First Schedule was added to the Bill.

The Second Schedule was added to the Bill.

## The Third Schedule

SHRI SRINIBAS MISRA: I beg to move:

Page 18, line 28,-
for "Government" substitute"Government" (60)

Page 10,
omit lines 5 to 9 . ( 61 )
Regarding amendment 60, as I have said, it should be plural; it should be 'Governments' and not 'Government', because we are saying 'States'. So, there cannot be only one Government.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKIA: I think, it is a proper and good amendment. We accept this.

SHRI SRINIBAS MISRA: I would like to speak on amendment 61. What are excluded from the purview of the Lokpal and Lokayuktas are given in the Third Schedule. Here (f) reads as follows:-
"Action taken in respect of appointments, removals, pay, discipline, superannuation or other matters relating to conditions of service of public servants but not including action relating to claims for pension, gratuity, provident fund or to any claims which arise on retirement, removal or termination of service."

This is self-defeating. If you are appointing Lokpal and Lokayuktas to look into the grievances and allegations of public servants, the citizens of this country, it is not proper that you should exclude these matters from the purview of the Lokpal and

Lokayuktas. Therefore, my amendment is that this portion, namely, (f), lines 5 to 9 on page 19, should be omitted.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: This amendment is not acceptable to us because if the personal matters of government employees are also included in the purview of Lokpal and Lokayuktas, it will make the work of Lokpal and Lokayuktas very cumoersome. Therefore, we have excluded all the personal matters relating to government servants except those which relate to pension, gratuity and provident fund of ex-government servants. Amendment 61 is not acceptable to us.

SHRI SRINIBAS MISRA: I want my amendment 61 to be put to the vote of the House.

MR. CHAIRMAN: I now put amendment 61, moved by Shri Srinibas Misra, to the vote of the House.

Amendment No. 61 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:
Page 18, line 28,for "Government" substitute-
"Governments". (60)
The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That the Third Schedule, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA:
I move:
"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:
"That the Bill, as amended, be passed."
SHRI RANGA (Srikakulam): i think that the House has very good reason to congratulate itself on this Bill not that it is

MR. CHAIRMAN: I want to draw your attention to one thing. This is third reading. It is not like the first reading. It is much shorter, only referring to maters which are referred to in the second reading. It should not be a long speech.

SHRI S. S. KOTHARI: I want to speak on the Third Reading.

SHRI SRINIBAS MISRA: A question was asked by an hon. Member from the DMK to know the meaning of Lokpal and Lokayukta. My mother tongue is something which is born from Sanskrit. I understand Lokpal, but this Lokayukta is very difficult for me to understand. The hon. Member has asked ten times so that the hon. Minister may give the meaning. Now, without understanding the meaning of Lokayukta, we are going to pass the Bill in the third reading.

SHRI RANGA: As I said, the House has very good reason to congratulate itself upon this Bill; not that it is entirely satisfactory, but it is because of the initiative taken by members of this House that the Government began to think on these lines and gave thought to the need for such a legisiation. I think that the chief credit should go to that grand old national ?eader, Mr. Munshi, for having for the first time placed before the pub?ic the details of this institution known as Ombudsman in Sweden and familiarise the idea of it and press upon the public mind the need for establishing an institution like this. Next. the late Mr. Mathur, who was one of our senior members here. moved a non-official resolution and extracted the promise from the Government that they would think about
this matter very seriously and take the necessary action. Then, the Administrative Reforms Commission came out with detailed proposals and a draft Bill also and gave a form to these two institutions in the manner in which they are indicated in this Bill as Lokpal and Lokayukta.

I agree with my friend, Shri Srinibas Misra, that it would have been much better for the Government to have chosen titles which would make a greater sense than these Sanskrit words and that would have pleased our friends from Tamilnadu also. Nevertheless, we need not quarrel over these names. I am extremely sorry that the Government has chosen to assert its innate conservatism that generally goes with any Government in its refusal to bring the Prime Minister and Chief Ministers within the mischief or within the ambit of this Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKI'A: This Bill has nothing to do with State administration. It is only concerned with the Union Government.

SHRI RANGA: The Prime Minister has not been brought within it. They thought so much about the Prime Ministership that they were not willing to bring the Prime Minister within the mischief of this Bill. As I said, it is a very conservative attitude because we discussed this matter in the Congress Working Committee of those days just when Mahatma Gandhi was still alive and soon after he died because by that time Congress Ministries had come. Just like a baby which no sooner it comes into the world starts crying, similarly these Ministers also $n_{0}$ sooner they become Ministers they begin to indulge in all sorts of wrong practices. Therefore, we wanted to have some check. Then we discussed it at great length. It is a long history. I need not go into that. In fact mentioned it in one of the Commonwealh Parliamentary Conferences also.

## [Shri .Ranga]

India has some history about this just hike so many other democratic countries. The only difference between India and other countries is while Sweden, New Zealand, England and Australia had taken early action, in order to bring this kind of a solace, this kind of an institution into existence and thus protect the people and assure them of some protection against arbitrary action, discrimination on the part of the Government and also corruption from Ministers, our Government had to wait all these years. Why? Because they had a very high, exalted view of the Ministers. So, Sir, Pandit Jawaharlal Nehru said, we cannot think of congress ministers becoming corrupt; and if, by any chance, one or two were to become corrupt, we cannot simply hand them over to some independent officer. So, he devised the idea that any complaint made against congress ministers-at that time we had congress ministers only and no body else in this country-should be dealt with by the Chief Mnnisters concerned. If there were any complaints against Chief Ministers they should be sent up to the Prime Minister here and if any complaints against the Central Cabinet Ministers were there, they should be dealt with by the Prime Minister. But, later on, what happened? We found one of the Prime Minister's personal secretaries indulged in ways of corruption and the Prime Minister was obliged to shed that Secretary and wash his hands off him. Some of the Prime Minister's own colleagues were charged for corruption but he tried to shield them for as $\operatorname{lon}_{g}$ as possible. He tried to shield the Chief Minister in Punjab as you know, till the very last moment. In the end he was forced to send his case to an ex-Supreme Court Judge and we know the results. That Chief Minister had to go. Similarly two Chief Ministers of Orissa had also to go. In that way Pandit Jawaharlal Nehru did not give satisfaction to the country nor did
his action bring any honour to hini or to the Parliament and that was the reason why when his successor Shri Lal Bahadur Shastri was Prime Minister and when a suggestion was made by Mr. Santhanam's Committee that the Prime Minister and the Chief Minister should be kept out of the purview of this particular legislation I tofd him that we were not prepared to accept it because we found that the Prime' Minister was capable of shielding ministers of doubtful integrity.

Now we come to the third Prime Minister. The third Prime Minister also wants to be kept out of the purview of this Bill. Let us hope that the third Prime Minister would be able to have a much better record than the earlier Prime Ministers so far as colleagues are concerned. Let us also hope-and it would be hoping against hope-that the Prime Minister herself or himself, would not indulge in such bad practices, undemocratic practices as to be charged by the people as undemocratic and discriminatory and dishonest. It is only hoping against hope and that is why I am extremely unhappy that the congress party here could not see its way to accept the amendments moved from this side that the Prime Minister also should be brought within the purview of this particular legislation.

So far as this legislation goes arenot quite sure that even these two institutions would be able to give greater satisfaction to the country than the vigilance commissions because it is a matter of time, how long they take to investigate into the complaints and give redress to the people concerned. The other is the question of the costs involved for the ordinary folk to have to invoke the aid of these institutions and place before them the whole of the case and all the evidence and all the rest of it, to prove the charges. Because, after
all, on these two anvils of time and of cost, the whole thing rests. If it costs too much or if the people cannot get justice quickly from these institutions, if these institutions were to indulge in too much of delay then, this entire system would fail to yield good results.

I hope, Sir, this Government would try to take the necessary precautions to ensure that not too much time would be aken and the procedure would not be.cumbersome and costly to the public in placing their complaints before this institution.

I once again remind the House of its debt of gratitude to Mr. Munshi and Mr. Mathur and I support this Bill.

धी शिख चन्द्र शा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का मोटे तोर पर समर्थन करता हूं। ड़स विधेयक की श्राषश्यकता होगी, यह बात भी साफ है। ग्राजादी के बाद हिन्दुस्तान में जैसी फिजा पैदा हुई है उसमें घ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है । ش्राज यदि सरकार को इस बात में खुशी है कि श्रष्टाचार रोकने के लिए एक विघेयक लाई है तो दूसरी तरफ सरकार दोषी भी हो जाती है वयोंकि ग्रब तक का जो सिलसिला देश में रहा इस हुकूमत की वजह से उससे श्रष्टाचार बढ़ा है, इस सरकार की नीतियों की वजह से हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार बढा है ।

सभापति जी, इस विधेयक में मिनिक्टर तक को नहीं छोड़ा गया है, लेकिन प्रधान मंत्री की इन्होंने चर्चा नहीं की है । उनको नहीं लाना चाहते हैं। मतलब यह है कि ग्राजादी के बाद बड़े से बड़े मिनिस्टर भी प्रष्ट हो गये हैं यह सरकार कबूल करती है इस विधेयक के जरिये। तो सरकार कंडेम्ड श्रोर गिल्टी है, इस से यह साबित होता है । ड्सलिए श्राप ने ऐसा कदम बढ़ाया ग्रीर आ्याप समझते हैं कि यह कारगर कदम होगा। तो फिर प्रधान मनी को इस दायरे

में क्यों नहीं लाये। चाहे मांजूदा प्रधान मंत्री हों, या ग्राने वाले प्रधान मंत्नी हों, उन सब को इस विधेयक में लाना चाहिये। यह सोचना कि प्रधान मंत्री दूध के घंगे हैं यह धारणा बिल्कुल गलत है। झ्रौर बराबरी की धारणा के भी गिलाफ है।

लेकन सवाल श्राता है कि श्रष्टाचा? इतना बढ़ा क्यों ? ग्राजादी के पहल भी वही लोग थे जो ग्राज श्राज़ादी के बाद प्रष्ट हो गये हैं, उन के खिलाफ शिकायतें हैं, चाहे प्रताप सिह कैंरों हों या श्री के० वी० सहाय हों, ग्राजादं के पहले उतनी खराबियां उ: में नहीं थीं । लेकिन क्या वजह है कि ग्राजादी के बाद यह खराब हो गये हैं, ओंर इन में खामियां क्यों अ्राने लगीं ? इसकी बनियादी वजह यह है कि ग्राजादी के बाद डस सरकार ने देश के सामने एक प्रेरणा रख़ने का काम छोड़ दिया है ।

ग्राजादी के पहलले सब कुरबानी देने के लिये जाते थे, उन को राज सत्ता से कुछ लेना नहीं होता था। बत्कि बलिदान की भावना रहनी थी। लेकिन झ्राजादी के बाद इन के सामने कोई श्रादर्श नहीं रहे, मकसद नहीं रहा, ग्रौंर वह प्रेरणा खत्म हो गयी । सोचा कि गह्दी पर श्रा गये जितना पैसा कमाना चाहो कमा लो । जो सिलसिला इन्होंने श्राजादी के बाद चलाया वह सिलसिला पूंजीवादी सिलसिला रहा जिस में ये खामियां भ्रानी हैं । खराबियां बढ़ी हैं नागरिकों के बीच में ही नहीं बल्कि राज्यों के बीच में भी, ग्रोर पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा होता ही है। इसलिये भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हिन्दुस्तान ही नहीं, स्वीडन् नहीं, जहां ग्रोम्बुड्समंन की शुस्त्र्भात हुई =ल्कि अ्रमरीका में भी ग्राप को भ्रष्टाचार की बात मिलेंगी। लेकिन एक फर्क श्राता है ग्रौर वह यह कि उन मुल्वों में जहां शिक्षा बढ़ी हुई है ग्रीर नैतिकता का स्तर कुछ ऊंचा है वहां छोटे प्रष्टाचार नहीं होते । यहा 5,10 रु० घूस लेने की बात होनी है,

## [श्री शिवषन्द्र श्ना]

ये सब बातें उन देशों में नहीं पायेंगे छोटा प्रष्टाचार वहां नहीं होता है। वहां प्रष्टाचार होजा है लाखों की जब बात भ्रानी है तब। नो पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से यह खराबियां हैं। जिस तरह से श्रोर मुल्कों में भ्रष्टाचार बढ़ा उसी तरह से यहां भी बढ़ा है। जिस में इजाफा किया है सरकार ने झ्रपनी योजनाग्रों से।

सवाल भाता है कि इस का हल क्या है ? हल यह है कि गंर बराबरी को बत्म किया जाय। श्रोर जब तक गैर बराबरी के सिस्टम को खत्म नहीं करते तब तक प्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। ग्रोर बानों के घलावा एक बात निहायत जरूरी है भ्रष्गचार को समाप्त करने के लिये श्रीर वह यह है कि श्रामदनी की सीलिग सरकार रखे।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया। लेकिन जब तक ग्रामदनी पर हदबन्दी नहों करते हैं एक अ्रीर दस के ग्रन्पात में. ग्रोर यह श्राथिक विषमता रहनी है नो इस के ननीजे ग्रोर भी खराब होते हैं ग्रोर भ्रष्टाचार अ्रागे बढ़ता है।

इसलिये मरकार यदि ईमानदारी से चाहनी है कि देग में भ्रष्टाचार का खात्मा हो, छोटे मे कमंचारी से लेकर मिनिस्टर तक कोई भ्रष्टनारारी न रहे, नो जिस तरह्ह से बैकों का राष्ट्रीयकरण किया हैं दृढ़ता के साथ उस श्रों कदम उठावे ताकि पूंजीवाद का खात्मा हो अ्रीर ममाजवादी व्यवस्था की शुरुस्रात हो। ग्रोर जब तक ऐसी फिजा पदा नहीं होती है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्रष्टाचार को रोकने की फिजा पैदा करने के लिये जो सरकार यह़ विधियक लंयी है उै उस वृष्टिकोण में में इस विधेयक का स्वागन करता हूं।
SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA (Anand): Eternal vigilarice is the price of liberty and democracy and I take it that this Bill cautions
and warns of corruption in high places. I must confess that standards in public life have gone down after Independence. Restraint should play a part in higher levels of society, especially the State Ministers and Central Ministers. The moment they attain a high position, instead of bringing about self restraint and discipline, they indulge in pomp and show. In order to save democracy and preserve the standards of public life this Bill has become necessary. It is welcome. But by itself, it will solve no problems. As a public servant of 38 years standing, I say that there are some standardas to be maintained; one's behaviour whether in power or out of power should be the same; simplicity should be the watch word. The differences in incomes, say of a person earning Rs. 30 lakhs a year and another earning Rs. 350 a year, create difficulties. The moment a person becomes a Minister, there are many temptations. If we lead a simple life. we can resist those temptations and not be corrupted. But when a person want more and more of comforts he yields to temptations and corruption. One of the causes of corruption is election. Our elections are becoming costlier every day and persons at high places are tempted to receive offers from business houses and others to meet the election expenses. It is good that there is a sode of conduct for the Ministers. We have the case of Orissa where the Chief Minister had his business while in Government Mere admonitions of fine of Rs 4000 or 5000 will not do: there will have to be stern punishment. There should be a higi standard among the public also. A corrupt man, more so in high places, should be put to public shame. I am of that opinion. Merely bringing litigation will not help or merely giving him some small punishment will not help. Corrupt people should be put to shame and should not be allowed to stand anywhere in public jife. In the olden days, they were publicly flogged and they were made to sit on the back of donkeys.

## 16 hrs.

## AN. HON. MEMBER: Black faces.

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA: Yes; what I mean to say is, the punishment should be so severe that they may not re-enter public life. I therefore welcome this Bill, and I hope our standards will improve and no Minister in any State or at the Centre will dare indulge in any sort of corruption.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): Sir, I should like to congratulate the Government on bringing this Bill, which should be of good service with regard to the eradication of corruption in sociecy. Actually, after Independence, corruption appears to have become all-prevading. With regard to Ministers, Gandhian principles are completely forgotten. The amount of corruption that was prevalent previously in some places has now multiplied itself.

But the main thing that arizes in this comnection is, is this Bill complete, and would it be successful in eradicating corruption? In $\mathrm{m}_{y}$ opinion, it is not complete in the sense that it does not provide for defferent punishment. That is a very important point. If somebody is found guilty, all that is done in the case of a civil servant is that he is made to retire p:ematurely or something is done to hush up the whole matter. The consequence is that the man does not worry, especially when he has built up sufficient fortune by wrong methods. He feels that the ultimate punishment is not going to be severe and so, why bother about it?

We have seen recently the report of the CBI, and it is found that about 99 per cent of the cases deal with small petty clerks or some supervisory grade staff. But when it comes to the higher ranks of the service, the CBI probably takes a lenient view or it does not make sufficient efforts to bring them to book. Even if they
are brought to book, they are transferred or a mild punishment is given. I think the Service Rules should also be amended, so that a civil servant may feel that if he goes corrupt, he is going to be punished and the punishment is gaing to be very stiff; and that would make him afraid of indulging in these acts.

Another important point which I would like to emphasise is with regard to public undertakings. That is a field where I have some experience. I am sorry to say that in that field also, corruption exists. It may not be in a big way, but it is there; there is no doubt about it. Part of the losses, if you analyse them, would be traceable to corruption. I may give an instance. In respect of a leading concern, the iron and steel goods are despatched by wagons. They reach their destination, and subsequently a note goes that the goods are defective; discounts and rebates for unjustified claims are given and considerable loss is insurred. This can be heard in the markets of big cities. (Interruption)

SHRI R. K. BIRLA: Why not you name the company?

SHRI S. S. KOTHARI: It is there; in the public sector. For instance, the Hindustan Steel. Let them look into it, if they have got the courage. In this case, discounts and rebates are claimed, and part of the claim is false or is exaggerated and a greater amount is paid than what is justified. That is one of the reasons why losses in such large concerns occur. Then, in respect of a concern in Bhopal, some bogus purchase bills have been entered in the books. It came to my notice that such things were induiged in. I hope that this will be looked into.

So, I would submit that with regard ${ }^{\prime}$ to public undertakings also, strict rules should be prescribed. Besides, efforts should be made to investigate

## [Shri S. S. Kothari]

and locate where corruption is taking place. With regard to agreements entered into by public undertakings, so many cases have come to light. I have introduced a Bill to the effect that public undertakings agreements should be properly scrutinised. But this Government does not want to take any action whatsoever. Wrong agreements are entered into, and even where the persons who had entered into those agreements are caught, they are allowed to go scot-free, and to join the very concerns and the contracting parties in whose favour they acted in a corrupt manner.

Therefore, unless the Government is seriously inclined to end corruption and unless the highest ranks in the civil service feel that it is their duty to see that their subordinates and other officers in the public undertakings do not resort to corrupt methods, I think any amount of Bills, and any amount of rules which are framed are not going to eradicate corruption. The spirit must be there; the will must be there. Most of the civil servants, who are in the higher echelons, are good honest people. They have come after much filtering. They must make it a point not to condone corrupt officers in their department but in the interest of the country, they must take action and end corruption.

Even with regard to the armed forces, I am sorry to say that cases are brought to light where goods are supplied to armed forces which are defective. If even military goods are defective, we can imagine to what extent degradation has taken place and how much corruption is pervading in society. In the case of the armed forces, I would think that the forces should have the power to take the strongest possible action against any person who is found to be corrupt; because if corruption exists in the armed forces, I do not know where it would lead this country to.

I have already dealt with the maistracy. Then I would say that an-
onymous complaints shoúld not be excluded. It is an important point. I would suggest that $a_{3}$ Committee of Parliament should be attached to the Lokpal and that Committee should examine whether there is a prima facie case or not. I feel that is necessary because the Lokpal is likely to be flooded with complaints and it will not be able to act properly. On the other hand, if there is a committee which can sort out the complaints, review them and, where a prima facie case appears to exist forward them to the Lokpal. That would ensure that the Lokpal is not over-flooded with complaints.

Lastly, the success of thi $\mathrm{S}_{\mathrm{S}}$ measure would depend largely upon the quality of the Lokpal or Lokayukta himself, They should be men of integrity, enjoying the highest possible standing in public life, with a reputation for absolute honesty. Only such people should be appointed to these posts and it should be seen, that they are not influenced by any person whatsoever. Because if they are influenced, they will not $\mathrm{b}_{\mathrm{e}}$ able to do justice to their job and the whole structure of the institution of Lokpal and Lokayukta, which we are trying to build, would be jeopardised.

SHRI P. VISWAMBHARAN (Trivandurm): Mr. Chairman, this is a very inadequate piece of legislation. It does not satisfy the requirements of the situation obtaining in this country today. As has been stated earlier, corruption is now all-pervading. Till a few years ago we used to hear stories of corruption only among Congressmen and Congress Ministers. Now that every party in India hascome into power in one State or another, the disease of corruption has spread into all parties. I confess that I also belong to a party which has got some partnership in administration in the State of Kerala. It is a sorry state of affairs that corruption has become so common and there is
no party which is free from that. All the same, I hold the Congress entirely responsible for the present state of affairs, because if they had given a clean administration during the last twenty years this disease would not have spread to the other parties.

The main adequacy of this Bill is the exclusion of the Prime Minister and Members of Parliament from the purview of this Bill. In my State of Kerala, the Public Men Inquiries Bill is before the State Assembly. When the Select Committee reported on that Bill, it included the Chief Minister, members of the State Legislature and the members of the panchayat samity and similar bodies within the purview of that Bill. But, after the report of our Joint Committee has come up, an attempt is being made to exclude the Chief Minister and the members of the legislature on the plea that they are excluded in the Lokpal and Lokayukta Bill.

The Minister, while replying to my amendment for the inclusion of Members of Parliament; did not give any reason; he simply said that this was considered by the Joint Committee and this suggestion was rejected. The entire Bill was considered, by the Joint Committee. So, it is not a proper g:ound to be advanced here. Anyway, this inadequacy is there and this has got to be removed and it should be made more perfect.

Still, as a step in the right dir 3 ction, I welcome this Bill and I request the Government to give a trial to this Bill, as has been said by Shri Kothari, by a sense of integrity and cent per cent respect should be given to the recommendations of the Lokpal and the Lokayukta. Under the Bill the Lokpal or the Lokayuktas could only make recommendations and it is for the competent authority to act. The competent authority is the Prime Minister or other competent authorities appointed by the Government. If those autho:ities fail to act according to the recommendations of the Lokpal or the Lokayukta, he can only
make a special report to the President. A special report to the President only means a report to the Government under the present system of our government. So, it is up to the Government to act on the recommendations or reports of the Lokpal and the Lokayuktas. I hope, the Government will give a fair trial to this and also come forward at the earliest available opportunity to include the Prime Minister and the Members of Parliament also within the purview of this enactment.

SHRI R. K. BIRLA (Jhunjhunl): Sir, while I support this Bill, I would like to know from the Government whether this Bill will be applicable to the armed forces also. I have very high regard and respect for all the three armed forces-the Navy, the Air and the Army. They are the defenders of our country. We know it very well. They have done a wonderful piece of job during the Chinese aggression as well as during the Pakistani aggression. I would like to know from Government whether there is going to be a separate Lokayukta for the armed forces or whether this will be applicable to the armed forces also.

Secondly, people have spoken very greatly about corruption. I know fully well that there is corruption practically in every sector, whether it is the public sector or the private sector, whether it is a Government official or a private official. What is the reason for this corruption? Why should there be such a great corruption in our country? The reason is that we produce less; there is less production of every article which is consumed by human beings.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: And poor distribution too.

SHRI R. K. BIRLA: Just a minute.
So, the first job for we people here $i_{s}$ that we must produce more and to the maximum. We must generate wealth in the country, whether it is in the private sector $o_{\text {: }}$ in the

## [Shri R. K. Birla]

public sector, whether it is by me or by my hon. friend who just now interrupted me. There must be more wealth in the country. The more the wealth in the country, I can tell you, there is going to be less and less corruption. That is all I have to say.

बो रामाबतार आास्त्री (पटना) : यह जो बिल है इसमें यत्नतत्न खामियां रह गई हैं । लेकिन मोटे तोर पर यह बिल सही है ग्रोर हम इसका समर्थन करते हैं ।

इसका समर्थन करते हुए में एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं । यह सही है कि जब तक हमारे देश की सामाजिक ब्यवस्था में श्रामूल परिवर्तन नहीं होगा, पूंजीवादी व्यवस्था को छोड़ कर समाजवादी रास्ते पर चलना हम शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार का श्रन्त नहीं कर मकेंगे। लेकिन जब तक वह स्थिति नहीं ग्रानी है तब तक यह बिल भ्रष्टाचार पर श्रंकुज लगाने का काम करेगा । लेकिन यहू तभी होगा जब इस बिल क़ो किताब के पन्नों में ही बन्द्द करके नहीं रख दिया जाएगा । ग्राप जानते हैं कि हमारे देश में मजदूरों के लिए, हरिजनों के लिए बहुत से कानून बने हु丁. हैं लेकिन उन पर श्रमल न होंने की वजद्र से उनको अ्रपना हक नहीं मिल पा रहा है । उनको जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है । इसको हम अंर ग्रांप श्रच्छी तरह मे जानते हैं । इस विल के साथ भी एेसा ही किया गया तो इस में बहुत सी ग्रच्छो बातें हुते हुए भी इसका कोई लाभ नहीं होगा । उस श्रवस्था में हम इसका प्रयोग भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में, घ्स लेने वालों को पकड़ने में, समाज विरोधी काम करने वालों को पकड़ने में नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हैं कि इसको ठाक तरह से कार्यान्वित किया जाए, इसको काम में लाया जाए। तभी हम, जो हैमारा सीमित उद्देश्य है, उसको हासिल कर सकेंगे ।

जो हमारा उद्देश्य है उसको हासिल करने के लिए इस बात की भी ग्रावश्यकत्ता है कि लोकपाल बहृत ही ईमानदार हो । इसको कई ग्रन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है। उसको ईमानदार ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसको जनता से भी सम्पर्क रबना चाहिए फॉर जनता की मुसीबतों को सिमझने वाला भी होना चाहिये, उसकी दिक्कतों को समझने वाला भी होना चाहिये। इसके साथ-साथ उसको जात बिरादरी, फिरकापरस्ती, सम्र्रदायवाद से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। भ्भगर वह इन सब बुराइयों से ऊपर नहीं होगा तो उसका जो पवित्न कर्तंव्य है, उसको वह निभा नहीं सकेगा । हम श्रोर श्राप जानते हैं कि पिछले दिनों बहुत बड़े-बड़े सरकारी क्रफसरों ने साम्र्रदायिक भाबना में बहकर साम्प्रदायिक दंगों में भाग लिया । इसका मबूत रांची का दंगा है या कोई श्रोर जगह का दंगा है। इस वास्ते लोकपाल को ईमानदार हो नहीं होना चाहिये, नीकरश्रियतित में दूर ही नहीं होना चाहिये, वर्कि जातपात ग्रीर फिरकापरस्ती की भावना से भी ऊंचा उठना चाहिये। वह ऐस्ना व्यक्ति होना चाहियें जो पक्क तीर पर धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हो। वह श्रष्टाचारी भी नहीं होना चाहिंये । ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि ग्राज जिन बड़े-बड़े नेताग्रों के हाथ में इस देश की बागडेंर है कल को उनका ग्रगर जनता अ्रपने बीच में से निकाल दे यानी चुनाव में हरा दे तो शुक्त जी उन लोगों में से किसी कों लोकपाल नियुक्त कर दें। गण्पा साहव जंसे किसी व्यक्ति को लोकपाल बना दें ग्रीर फिर वह वहां पर जा कर गोलगप्पे बांटने शुरू कर दे । उसको पार्टीबंदी से ऊपर उठकर काम करना चाहिये । लोकपाल किसी पार्टी विशेष के प्रभाव में नहीं होना चाहिये, किसी मंत्री विशेष के प्रभावं में नहीं होना चाहिये, किसी बड़े श्रफसर विश्रेष के प्रभाव में नहीं होना चाहिये ।

### 16.16 bess.

[Shri Prakash Vir Seastri in the Chair ]

श्राज क्या होता है ? हमारे देश में एंटी कुरप्शन डिपार्टमेंट बने हुए हैं। लेकिन उनके द्वारा बड़े लोग नहीं पकड़े जाते हैं । जो त्रोटे-छोटे कर्मषारी होते हैं उन बेचारों को कहा जाता है कि तुमने पांच रुपये घूस लो है, दस रुपये घूस ली है श्रोर उनको पकड़ लिया जाता है ग्रौर डनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है । मुझे ग्रपने सूबे का घ्रनुभव है। एक एस डी श्रो के मामूली पेशकार ने पांच रुपये घूस ली श्रोर उसको दो साल की सत्रा करवा दी गई श्रोर उसकी नौकरी बीन ली गई। ऐसा न हो कि बड़ी मब्नलिखां छूट जायें श्रोर छोटी मछलियों को बकड़ने लग जाएं । श्रगर लोकपाल ठीक नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, इन सब बातों से ऊपर नहीं होगा, जनता के सुख्खदुख को समकने बाला नहीं होगा तो बह इस तरह की गलतियां कर सकता है जो साधारण कर्मचारी हैं उनको तो पकड़ लिया जाएगा श्रौर जो बड़े लोग हैं वे बच जायेंगे । बहुत से लोग कहते हैं कि छोटे लोग कचहंरियों में वैसे मांगते हैं। ऐसे मामले भी कहीं-कहीं होते होंगे । लेकिन इसका इलाज यह् है कि उनको श्राप बीवनयापन योग्य पैसा दें, मिनिमम बेज ग्रावए्यकता के श्राधार पर दें। उनकी तरफ से यह मांग उठाई जा रही है । 27 लाख केन्द्रीय कर्मचारी इस मांग को लेकर ग्रान्दोलन कर रहे हैं। 19 सितम्बर, 1968 को उन्होंने हड़ताल भी की थी । उनकी जो दिक्कतें हैं उनको श्राप दूर करें । उनकी दिक्कतों को श्राप दूर नहीं करेंगे लेकिन वे ग्रगर कुछ गलती करेंगे तो ग्राप उनको पकड़ लेंगे । बड़ेन्बड़े मगरमच्छ जो हैं, बड़ी-बड़ी मछलियां जो हैं वे तो बच जाएंगी जैसाकि हम ग्रपने सूबे में देख रहे हैं लेकिन ये पकड़ लिये जायेंगे । ये वे मगरमच्छ हैं जिन्होंने लाखों ग्रोर करोड़ों रुपया हड़प लिया है ।

मेरा निबेदन है कि सर्ग्कार इस विष्षेयक को लागू करते समय इन तमाम बातों को ध्यान में रबे ग्रोर पूंजीवादी ममाज बनाने की श्रपनी वर्तमान नीति को तिलांजाल दे दे । यह झ्रच्छा है कि उसने बैकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है । उसके बाद बह विदेशी व्यापार का भी राष्ट्रीयकरण कर दे 1 ग्राज बंगाल में चाय बागान में, जो कि श्रंश्रेज पूं जीपतियों के हाब में हैं, दो लाख मज़दूरों की हड़ताल चल रही है । सरकार उन टी प्लान्टेशन्ज्व को भी हाब में ले ले । इसी प्रकार वह विदेशी तेल कम्पनियों श्रौर गल्ले के थोक ब्यापार को भी अ्रपने हाष्ष में ले ले । पब्लिक सेक्टर में जो स्टील के कारखाने हैं, उनके श्रतिरिक्त प्राईवेट तेष्टटर में टाटा बैंे हुए हैं, जिनका चाबृंक राष्ट्रपति के घुनाव में चल रहा है। सरकार इन कारखानों का मी राष्ट्रीयकरण करे ।

ह. यदि सरकार सचमुच में ये कदम उठा कर समाजबाद की तरफ़ बढ़ेगी घ्रोर ध्रष्टाचार का धन्त्र करेगी, तमी इस विधेयक के सीमित उद्देश्य की पूरित होगी ।

इन शब्दों के साष मैं इस विषेयक का 'समर्यन करता हूं ।

भी अ्रनुर गनी डार (गुड़गांव) : सभापति महोदय, में यह बिल लाने के लिए सिदकदिली से श्री शुक्ल को मुबारकबाद देता हूं । इतिहास में उनके नाम के साथ हमेशा इस बिल का ज़िक किया जायेगा, जिसके पास होते ही, मेरा यकीन है, पचास परसेंट करप्शन ग्रपने श्राप खत्म हो जायेगी। ग्राबिर हुकूमत का एक जलाल होता है, वर्ना बीस सिपाही कैसे लाखों ग्रादमियों को सम्भाल सकते हैं । इस बिल को लाने के मानी ये हैं कि गवनमेंट करप्शन को खत्म करने पर तुल गई है ।

यह ठीक है कि इस बिल में तुटियां हैं मैं चाहता था कि यह कानून हम पर लागू हो - अ्रौर प्रधान मंनी पर भी लागू हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । मैं बताना चाहता हूं कु किसी वक्त प्रधान मंत्री का ईमान गराने
[ध्री श्रबनुल गनी डार]

बयाल यह्ह था कि पंजाब के चीक़ मिनिस्टर ने एब्यूज्त झ्राफ़ पावर नहों किया ग्रोर वह नेक हैं, जबकि हमारा विचार था कि उन्होंने एब्यूत ग्राफ़ पावर किया । प्रधान मंत्री हैं ने हमें बहुत कुछ कहा। लेकिन ग्रदालत का फ़ैसला प्रघान मंती के ख्याल के खिलाफ़ था ।

में कहना चाहता हूं कि यह जस्री नहों होना चाहिए कि कोई एलीगेशन्ज्ज करे ही, त्भी लोकपाल उन पर तवज्जह दें। कई बातें श्रब्बबारों में ग्रा जाती हैं। मैंने 19 मार्च के स्टेट्ममैन में एक निराली खबर देखी। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रपनी को-ग्रापरेटिव कनज्यूमर्ञ सोसायटी के श्राडिट्टि के लिए एक ऐेेे जरुा को श्राडिटर मुक्रंर किया, जिसकी काफ़ी घ्ररसे से गवनंमेंट के यहां इज्जत है । उसने 1966-67 की रिपोर्ट अ्रगस्त, 1968 में दे दी । में कोई सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस रिमोर्ट में बताया गया कि बहुत सी गलतियां हैं ।

रजिस्ट्रार साहब ने यह समझ़कर कि श्रगर गवर्नमेंट तक वह रिपोर्ट जायेगी, तो काफ़ी नुक्सान होगा, उस रिपोर्ट को दबा दिया हालांकि उसके लिए 尹्माडिटर को 6500 रूपये की फ़ीस दी गई थी। उसके बाद रजिस्ट्रार साह्ब ने बिल्कुल ग्रपने माले को-सारी बुदाई एक तरफ़, बोबी का भाई एक तरफ़श्राडिटर मुकर्रे कर दिया । पहले श्राडिटर को 6500 रुपये फ़ीस दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट ग़ायब कर दी श्रोर उसके बाद दूसरे झ्राडिटर को फ़िर फ़ीस देकर् नई रिपोटं तैयार करवा ली ।

इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जहरी नहों होना चाहिए कि कोई ग्रपनी ऐलीगेशन्ज्र लिख कर भेजे ग्रोर यह भी जहूरी मही होना चाहिए कि वह् ग्रपना नाम लिखे । ग्रगर लोकपाल या सरकार के नोटिस में इस किसम की कोई बात ग्रा जाये, तो उसके बारे में जक्र तहकीकात की जानी चाहिए ।

मेरे दोस्त, झा साहब, ने बार-खार बड़े बड़े मगरमच्छों का जिक्र किया है । गवर्नमेंट को इस बात का पता लगाना चाहिए कि श्रगर किसी ने सनग्रत को तरक्को देने के लिए, मज़दरों को काम देने के लिए या फ़ौज या, पुलिस को वर्दी वग़ँरह देने के लिए नाइलोन ग्रोर वूल टाप्स को इन्पोर्ट किया, तो क्या उस कच्चे माल का उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। मेरे जसा श्रादमी छस बारे में किताबें ग्रोर सुबूत वर्गरह कहां से लाये ? सरकार इलैक्ट्रिसिटी की किताबें मंगाये । वे सरकारी किताबें हैं म्रोर उनको बदला नहों जा सकता है । श्रगर इलंक्ट्रिसिटी का कनज़म्प्शन हुग्रा है, तो यकीनन. उस माल को उस मक्रसड के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए उसको इम्पोर्ट किया गया था। चाइना के साथ लड़ाई के वक्त डिफेंस के नाम पर पचास लाख रुपये के नाइलोन श्रोर वूल टाप्स मंगाये गये थे, लेकिन डिफेंस के लिए धेले का भी इस्तेमाल नहीं किया ।

खुदा शुक्ला जी को मेरी जिन्दमी दे । उनकी गवर्नर्मेंट कामयाब हो। श्रगर वह मुझे कहें, तो में एक खाका दे दूंगा कि किसने ब्लंक में कितना रुपया कमा लिया। उस रुपये में से कुछ तो उन लोगों की जेब में गया, कुछ ग्रफसरों की जेब में गया ग्रोर कुछ एक-प्राध्र मिनिस्टर या दस मिनिस्टरों, की जेब में गया ।

ग्राखिर में में ग्रापका शुक्रिया ग्रदा करता हूं ग्रोर शुक्ला जी के लिए चाहता हूं कि मेरी उम्य उम्हें लग जाये प्रौर वह नेक काम करते रहें ।


 ديتا هور - أها





 هير -'ب




 !





 فimat
 خلاف تها -


 ديى - كئى باتير اخهارو مهي آن












 تو كافى زتصطان هرها - اس, (يورث كو كو دبا




 ك


 تهار كروا لى -









مير< موست - جها ماحب -
 مـ -




ناكُون او, وول شالهن كر امهورت كيا -

 آدمى اس بارع مين كتابيا اور ثبوت



 تو يقيلاً اسل ملا كو اس اس متصد ع لُّع





 كيا كيا
-

 كه كس


 ملستر - يا دس ملسترور - كى جهب ميّ





भी वेणी अंकर शर्मा(बंका) : सभापति महोदय, इस बिल के मूलमूत सिद्धान्तों से अ्रपनी सहमति प्रकट करते हुए में इस का स्वागत करता हूं । मेरे विचार में यह बिल बहुत पहले मा जाना चाहिये था, क्योंकि बिना बोजना क्रैर प्सार्निंग के भारतवर्ष में श्रमर कोई चीज बढ़ी है श्रोर पनपी है तो वह है प्रष्टाचार, बेईमानी, शैतानी श्रोर घूंसधोरी । इस का एक कारण यह मी है कि चूंकि हमारे बहां प्राडकश्न की कमो है, इसलिए प्रापर डिस्द्रीब्यूशन के लिए हम ने एक तरह से लाइसेंस श्रोर परमिट का राज्य कायम कर दिया , जिसकी बजह से हमारे यहां प्रष्टावार मौर घूंसखोरी बढ़ी। जहां हम इस बिल के ह्दरा प्रष्टाचारियों को सजा देने की बात सोच रहे हैं, बहां हमें प्रष्टाचार के कारणों को मी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम लाइसेंस श्रोर परमिट की ख्यवस्था को बन्द नहीं करते हैं, तो प्रष्टाबार बढ़ता ही रहेगा श्रोर चाहे हम कितने ही लोकपाल भ्रोर सोकायुक्त नियुक्त करें, यह बोमारी दूर नहीं होगी। मानमीय खाद्ध मंतो ने एक बार कहा था कि चूंकि खाब्टि स्थिति सुषर रही है हम श्रागे चल कर फूड जोन्ज को हटा देंमे। में समझता हूं कि ऐसा करने से कम से कम एक विभाग में प्रष्टाचार में तो कमी हो जायेगी।

प्राइम मिनिस्टर अ्रौर पार्लियामेंट के सदस्यों को इस बिल की परिषि में नहीं रखा गया है । मेरी दृष्टि में यह एक ऐसा कदम है, जिसके लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। श्राज तो यह शवस्था हो रही है कि बाड़ ही खेत को खा रही है। जो हमारे रक्षक हैं, वे ही भक्षक हो जाते हैं। में प्राइम मिनिस्टर की व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कहता हू, बल्कि में प्राइम मिनिस्टर के मोहदे की चर्चा करता हूं । श्राज की प्राइम मिनिस्टर श्रच्छी हैं । पहले के प्रा巨म मिनिस्टर भी बहुत श्रच्छे थे । लेकिन श्रागे चल कर ऐसे प्राइम fिनिस्टर श्रा सकते हैं, जिन के श्राचरण के बारे में स सन्देह हो।

इसलिए प्राद्रम मिनिस्टर घोर पालियामेंट के सदस्थों को इस बिल के कार्य-क्षेत्न से मुक्त रबना बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि पार्लयामेंट के मेम्बर भ्रगर मुक्त हो जाते हैं तो एम० एल० एज० मी स्टेट्स के ऐसे बिलों के दायरे से मूक $I$ कर दिए जाऐंगे भ्योर चीफ मिनिस्टर्स भी छोढ़ दिए जाएंगे 1 यह मी हमने देखा है कि घ्रष्टाचार श्रौर घूंसब्बोरी के मामले में, लाइसेंस ध्रोर परमिट बिलाने में जितने एम० पी० भ्रोर एम० एल० एज० दक्ष होते हैं भोर वे जितना मागे पीछे काम करते हैं उतना भोर कोई नहीं करता। इसलिए कम से कम इस बिल का उद्देश्य पूरा हो भोर इस बिल से देश को लाम हो इस के लिए मिं चाहूंगा कि पारालयामेंट के मेम्बर म्रोर प्राइम मिनिस्टर को मी इस बिल की परिधि में श्रामिल किया जाए श्रोर जब यह होगा तो यह निश्चित है कि जो स्ट्ट्स में कानून बनेंगे उस में जो एम० एल० एज० हैं भोर चीफ मिनिस्टर्स हैं बे स्वयं ही उनके दायरे में श्रा जाएंगे। इस बिल के दायरे से प्राइम मिनिस्टर घोर मेम्बस्स म्राफ पालियामेंट को श्रलग कर देने से में समक्षता हूं स्वभावत: स्टेट्स में भी चीक मिनिस्टर्स ग्रोर एम० एल० एज० म्रलग रबे जाएंगे । इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिजों कों इस बिल के दायरे से घलग रबना मैं समझता हूं बहृत बुरा होगा ग्रोर इसलिए मैं माननीय गृह मंनी से प्रार्षना करूंगा कि कम से कम हन दोनों बातों पर वे फिर से विचार कर के इन्हें स्वीकार करेंगे। क्योंकि भ्रन्त में जो राम राम करता है उसी की मुक्ति होती है । इसलिए यदि बिल के इस तृतीय वाचन में भी वह इस को मान लेते हैं तो देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा ।

शी विस्षा चरण शुबल : सभापति जी, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ग्राभारी हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से इस विधियक का समर्थन किया है । माननीय रंगा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि इस में प्रधान मंनी जी को शामिल करना चाहिए था। प्रधान मंनी जी को क्यों हम शामिल नहीं कर सके

इस विध्यक के श्रन्त्रंत इस के बारे में काफी विस्तृत रुप से यहां पर बताया गया है ग्रोर में समझता हूं कि उस के बारे में एक जनरल ऐपीमेंट मी है कि प्रधान मंनी के पद को इसमें शामिल करने से बहुत सी ऐसी कठिनाइयां पैदा होंगी कि जिस से हमें इस बिल को लागू करने में बहृत कठिनाई होगी। मे यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि यह बात नहीं है किं वर्तमान प्रधान मंती इस बिल में प्रधान मंती के पद को सम्मिलित नहीं करना चाहतीं। इस के विपरीत वंतमान प्रघान मंत्री यह् चाहती थीं कि किसी तरह से हैस बिल में. प्रधान मंती को सम्मिलित कर लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा। पर जब हम ने उन को बताया कि क्या कारण हैं, किन कारणों से हम सामिल नहीं कर रहे हैं तब उन्होंने कहा कि ठीक है, न शामिल किया जाये। यदि देखा जाय तो उन की रुचि तो इस बात में थी कि इस बिल में प्रधान मंती को मी सम्मिलित करना चाहिए। पर जैसे कि कारण पहले बताए गए हैं, में उनको दोहराना नहीं चाहता, उन कारणों से इस बिल में प्रधान मंत्री को श्कामिल करना श्रावश्यक नहीं समझा गया घ्रौर मैं समझ्कता हूं कि उन को शामिल करने से हमारा जो बिल का उद्देश्य का उस में बहुत हानि होती।

भी बाकर प्रलो मिर्बा (सिकन्दराबाद) : चीफ मिनिस्टरों का क्या होगा ?

ध्री विध्धा चरण घुक्स: वह तो राज्य सरकारें जब श्रपने श्रपने कानून बनाएंगी तं उस में वह प्रावषान करेंगी। केरल में उन्होंन कानून बनाया है तो उस में उन्होंने चीफ मिनिस्टर को सम्मिलित किया है । दूसरी जगह वह कानून बनएएंगे तो स्वयं निर्णय करेंगे कि उन्हें शारिम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ।

रंगा जी ने दूसरी बात यह कही किं हमें यह देखना चाहिए कि इस की कीमत कहीं इतनी ज्यादा न हो कि गरीब लोग इस प्रावबान का फायदा न उठा सकें श्रौर दूसरी बात
[.श्री विद्य चरण शुक्ल]

यह कि इसमें इतनी देर न हो इस काम में कि जिससे काम की उपयोगिता ही नष्ट हो जाय। हम लोग इस का ध्यान रखेंगे भौर दस बिल़ के अन्दर जो प्रावषान किया है उसमें भी यह बात है कि कम से कम सर्चा हो मोर जल्दी से जल्द़ी इन चीजों का निणंय ट्रो सके। जब तक जल्दी निर्गय नहीं होगा तब तक इस बिल का जो प्रमुल उछेश्य है वह पूरा नहीं हो सकेगा।

श्री हिव चन्द्र झा ने श्रपनी बहस शुरु करते हुए कहा कि इस बिल का मतलब यह होता है कि बहुत्त ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे देब में फेला हुग्रा है। मं इस बात को नहीं मानता हुं कि यह बिल उस बात का सबूत है कि भ्रष्टाचार बहुत उतादा देश्र में फलला हुग्रा है । इस बिल का मुल्य उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार को हटाना ही नहीं है। इस बिल का उद्देशय यद्र भी है कि जो ग्रनाप शनाप श्रारों गैरजिम्मेदारी से लगाए जाते हैं उन का भी इलाज इस के द्वारा हो क्योंकि जब लोक पाल प्रीर लोकायुक्त के पास इस तरह की चीजें जाएंगी तो वह हस बात का फैसला कर सकेंगे कि जो श्रारोप लगाए गए हैं उन में कोई सत्यता है या नहीं, उन में कोई तथ्य है या नहीं । या बिलकुल हो निराधार श्रौर गलत श्रारोष लगाए गए हैं। म्र.ज इस तरह की कोई एजेंस़ी या मशीन हुमारे पास नहीं है। ग्राज यदि किसी मिनिस्टर या अ्रधिकारी पर कोई श्रारोप लगाया जाता है तो सरकार को स्वयं निर्गय करनापड़ता है कि प्राइमा फेसी कोई केस उसमें है या नहीं, कोई इस तरह को गुंजाइइ इस के श्रन्दर है या नहीं कि इस के लिए कोई नियमित स्प से जांच पड़ताल की जाय या नहीं। पर जब लोकपाल झ्रौर लोकायुक्त की संस्था हमारे सामने श्रा जायगी तब इस बात की मुविधा हो जायगी कि हर एक मसले को जो कि उन के कार्यक्षेत्र के अ्रंतर्गत ग्राता है उस के ग्रन्दर हम इस को भेज सकें ग्रोर उनके द्वारा इस की जांच पड़ताल करवा लें कि जो भी संसट् सदस्यों द्वारा या कि.सी भी जिम्येड्डर व्यक्ति के द्वारा ग्रारोष

लगाए गए हैं उनमें कितना तथ्य है घोर उस से आ्रागे हम लोग क्या कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिए यह कहना कि यह घष्टाचार जितना बढ़ा हुद्या है उस को यह बिल दिसाता है यह बात नहीं है। यह गैर जिम्मेदारी के जो भ्रारोप लगाए जाते हैं सार्वजनिक कायंकर्ताम्मों के ऊपर भ्रोर सरकारी अधिकारियों पर जो कि एक कहिन कार्य का निर्वाह करते हैं इस देश के भ्रन्दर, उनके ऊपर से वह सन्देह दूर हो सके इस काम में भी यह विधेयक सहायक सिद्ध होगा ।

कोठारी जी ने यह कहा कि इस के लिए कोई संखद की ए₹ समिति ₹ंठा लेनी चाहिए। में कहना चाहता हूं कि संसद को इस बात का ग्रांधनार है कि कोई भी उस के पास रिपोर्टं श्राती है तो संसद स्वष्ट निण्णय क.र के कि.ड़ी भी समिति की स्यापना कर सकती है ग्रोर वह नंमिति उस की जांच पड़ताल कर सबती है । उस के लिए इस क.नून में प्रावत्रान करना में तो डीक नहीं समझत़ा प्रोंर न नें यह समझता हूं फिं वह श्रावृ्यक है।

जहां तंi कि तोकपाल श्रोर लोकायुक्त के मधिनारियों का सवाल हैं कि नि स ब्पक्ति को बनादा जाय उसं में सें समझता हूं कि जो प्रावधन इस बिल में किया गया है उस से इस बात की सु वृता होगी ग्रौर हमें उस में सहायता मिलेगी कि हमारे देश के श्रच्छे से ग्रणंडे जो व्यक्वित हैं उन को इए तरह का ऊंचा पद दिया जाय । इस के लिए इस बात का प्रावधान किया गया है कि एक तो सरकार की तरफ से दूसरा विरोधी दल की तरफ से भौर तोसरा जो भारत के मुछ़य न्यायाधीश हैं उनकी तरफ से कोई नाम ग्राए तो उस को मंज़्र कर के हम लोरपाल क. पद ₹ें ग्रोर इसो तरह से लोकायुक्त का पद दें । इम से यह बान हम लोगों के मन में जम सवती है कि जो भी न्यक्ति इस तरह से चुना जायगा वह ऐसा होगा जिस के श्राचरण के संबंध

में, जिस के चरित्न के संबंध में म्रोर जिस की यच्चाई के संबंध में जरा भी शक किसी को नहीं होगा श्रोर इस की सफलता भी इसी पर ग्राषारेत है । यदि लोकपाल के ऊपर सन्देह होने लगे कि किसी मंबो या ग्रधिकारी से वह प्रमावित हो सकता है या उन के दबाव में वह् ग्रा सकता है तब तो जो भी विश्वास थोड़ा बहुत सरकार के ऊपर है कि बह त्रष्टाचार को रोक्ना चाहती है बह भी हट जाएगा अ्रोर इस बिल का कोई मतलब नहीं रहेगा । इसलिए में समझ्सता हूं कि यह बात बहुत श्रावश्यक है कि जो भी व्यक्ति इस पद पर निय्क्त हो वह ऐसा हो कि जिस के ऊपर सबंसम्मति से सब लोग विश्वास कर सके भ्रोर कोई कंड़ीवर्सी उस के संबंघ में न हो ।

बाकी रामावतार जी ने भीर दूसरे सदस्यों ने बहुत लम्बी लम्बी श्राधथक व्यवरथा की बातें कहीं। में समझता हूं कि उन का संबंत्र हमारे यहां प्रष्टाचार के जो मामले अ्राते हैं जन से होता है लेकिन जहां तक हमारे इस विधेयक का संचंध है इस से उस्त को कोई fिशฐे मतलब नहीं है। में जानता हूं कि उन बातों पर हमें सोच विचार करना होगा। में यह भी जानता हूं कि यह बिल स्वयं पास हो कर सम्पूर्ण रूप से जो क्रृष्टाचार के मसले हैं उन का समाधान नहैं दे मकता। उस के लिए हमें ग्रोर भी दूपरे समाधान बूंढ़ने होंगे । में समझता दूं कि यह विल उचित दिशा में एक कदम है श्रोर तेगा नहीं हैं कि सम्पूर्ण गममस्दा इस कदम से हल हां जायगी। पर उंचत दिशा में एक डचित ददम होने के नातें से हमें खुशी है वि गम्पूर्ण सदन ने इन विनेयक का स्वागत किया है म्योर मैं उन्मोद करता हूं कि इस विधेयक को सवंसम्मति से पास किया जायगा ।

समापति महोदय : प्रश्न यह है कि यह

विधेयक जो संशोधित रूप में श्रापके सामने प्रस्तुत है, इस पर सदन श्रपनी़ स्वीकृतित दे।

The Motion was adopted.

### 16.38 hrs.

## DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY <br> GRANTS (RAILWAYS), 1969-70

1, सभापति महोबय : शब यह सदन 1969-70 के रेलने बजट संबंघो भुनुदानों की श्रनुपूरक मांगों पर विचार करेगा।

Demand No. 2-Miscellaneous ExPENDITURE

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

'That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of 'Miscellaneous Expenditure'."

## Demand No. 15-Open Line WorksCapttal, Depreclation Restrve Fúnd and Development Fund

MR. CHAIRMAN: Motion moved:
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of 'Open Line Works-Capital, Depreciation Reserve Fund and Development Fund'."

इस के लिए एक घंटा नियत हुश्रा है । जिन सदस्यों ने कटोती के प्रस्ताव दिए हैं ग्रोर उस पर कुछ कहना चाहते हैं वह श्रपनी चिट भेज दें जिस से उनहें कुछ कहने का घ्रवसर दिया जाय। जो कटौरी के प्रस्ताव
*Moved with the recommendation of the Chief Justice discharging the functions of the President.


[^0]:    *The following Members also recor ded their votes:-
    AYES: Sarvashri Om Prakash Tyagi and Ram Gopal Shalwale;

